राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, गुरुवार, 20 नवंबर 2025

वर्ष 14,अंक 217, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

कार्यवाही की मांग को लेकर सड़क जाम..03

मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगा दिखा ट्रैक्टर ट्रॉली पर भर रहे सवारियां..04

वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 15वें वर्ष गिरावट, भारत आंशिक रूप से स्वतंत्रः फ्रीडम हाउस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन फ्रीडम हाउस ने कहा है कि वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार पंद्रहवें वर्ष गिरावट आई है. 72 में से 27 देशों में गिरावट देखी गई है, जबकि भारत 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' बना हुआ है और 51वें स्थान पर है. आखिरी बार संगठन ने 2021 में भारत को इंटरनेट नियंत्रण में 'स्वतंत्र' दर्जा मिलने का दावा किया था. फ्रीडम ऑन द नेट 2025 रिपोर्ट के अनुसार, जैसे-जैसे सत्तावादी सरकारों ने ऑनलाइन आयोजित विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सेंसरशिप और ऑफ़लाइन दमन का इस्तेमाल किया, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को डिजिटल अभिव्यक्ति पर प्रतिबंधों में वृद्धि का सामना करना पड़ा है. इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन स्पेस में पहले से कहीं अधिक हेरफेर किया गया है, क्योंकि अधिकारी पसंदीदा नैरेटिव को बढ़ावा देने और सार्वजनिक चर्चा को विकृत करने की कोशिश करते हैं. रिपोर्ट में पाया गया कि जिन 18 देशों को 'मुक्त' इंटरनेट स्वतंत्रता का दर्जा प्राप्त है, उनमें से आधे देशों के स्कोर में कवरेज अवधि के दौरान गिरावट आई है. रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच, केन्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, बांग्लादेश ने 'वर्ष का सबसे मज़बूत सुधार हासिल किया है, क्योंकि छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह ने अगस्त 2024 में देश के दमनकारी नेतृत्व को उखाड़ फेंका.' चीन और म्यांमार 'इंटरनेट स्वतंत्रता के लिए दुनिया के सबसे खराब वातावरण' बने हुए हैं, जबकि आइसलैंड में सबसे मुक्त ऑनलाइन वातावरण पाया गया. भारत के मामले में रिपोर्ट में पाया गया कि देश में ऑनलाइन सूचना वातावरण फेक न्यूज और भ्रामक सामग्री से भरा हुआ है, खासकर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था।

सोशल मीडिया एआई-जनित या भ्रामक वीडियो और सूचनाओं से भरा हुआ था, जिसमें दोनों देशों के प्रभावशाली लोग और सरकार समर्थित संस्थाएं भड़काऊ और भड़काऊ सामग्री की बाढ़ ला रही थीं. रिपोर्ट में कहा गया है, 'अप्रैल 2025 में कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, तो दोनों देशों में सरकार से जुड़े प्रभावशाली लोगों और टिप्पणीकारों ने भड़काऊ और एआई-जनित सामग्री की बाढ़ ला दी, जिससे समाचार और सूचना के विश्वसनीय स्रोत गायब हो गए.' 9 मई को पाकिस्तान द्वारा एक भारतीय रफाल विमान को कथित तौर पर मार गिराए जाने के बारे में सीएनएन की एक रिपोर्ट पर आधारित एक समाचार रिपोर्ट के कारण द वायर की वेबसाइट भी कई घंटों तक अवरुद्ध रही. इसके अलावा, अगस्त 2025 में रिपोर्ट की कवरेज अवधि के बाद भारतीय अधिकारियों ने बताया कि स्टारलिंक ने भारतीय कानून के अनुपालन में स्थानीय यूजर्स का डेटा भारत में संग्रहीत करने पर सहमति व्यक्त की है. यह तब हुआ जब सरकार ने जनवरी में उपग्रह सेवा के गैरकानूनी उपयोग की जांच शुरू की थी. डेटा गोपनीयता के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां कमज़ोर क़ानून और व्यापक सरकारी निगरानी वाले देशों में आयु-सत्यापन कानूनों का दुरुपयोग होना स्वाभाविक है, वहीं मज़बूत गोपनीयता कानूनों वाले देशों में भी साइबर सुरक्षा उल्लंघन होते हैं।

भारत की आधार प्रणाली का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे इससे जुड़े थर्ड पार्टी डेटाबेस में कई बार डेटा उल्लंघन हुए, जिसके परिणामस्वरूप लाखों आधार संख्याएं लीक हो गईं, जिससे धोखाधड़ी और साइबर अपराध में वृद्धि हुई. इसी तरह, अमेरिका में अगस्त 2025 में यह बताया गया कि अमेरिकी दूरसंचार अवसंरचना में घुसपैठ करने के लिए एक वर्षों लंबे अभियान - जिसे साल्ट टाइफून कहा जाता है - ने चीनी सरकार से जुड़े हैकरों के एक समूह को करोड़ों अमेरिकियों से संबंधित डेटा चुराने में सक्षम बनाया. यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी देश की सरकार द्वारा लागू किए गए छह प्रमुख इंटरनेट नियंत्रणों में से भारत सभी का उपयोग करता है - सोशल मीडिया या संचार प्लेटफार्मों पर राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक सामग्री की नाकाबंदी; आईसीटी नेटवर्क को जानबूझकर बाधित करना; सरकार समर्थक टिप्पणीकार जो ऑनलाइन चर्चाओं में हेरफेर करते हैं; ब्लॉगर या आईसीटी यूजर्स को राजनीतिक या सामाजिक सामग्री के लिए गिरफ्तार किया जाना, कैद किया जाना या लंबे समय तक हिरासत में रखा जाना; ब्लॉगर या आईसीटी यूजर्स पर शारीरिक हमला किया जाना या उनकी हत्या (हिरासत में भी) शामिल है।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स मोदी सरकार की उस व्यवस्था को चुनौती दे रहा है जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों और पुलिस को एक वेबसाइट के ज़रिए, जिसे एक्स 'सेंसरशिप पोर्टल' कहता है, सीधे तकनीकी कंपनियों को सोशल मीडिया सामग्री हटाने के आदेश देने की अनुमति देती है. चीन, बांग्लादेश, क्यूबा, ईरान, म्यांमार, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और वेनेजुएला ऐसे अन्य देश हैं जो इंटरनेट की आज़ादी को प्रतिबंधित करने के लिए इन छह नियंत्रणों का इस्तेमाल करते हैं. इस बीच, रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट नियंत्रण के मामले में आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कोस्टा रिका सबसे स्वतंत्र देश हैं. गौरतलब है कि पिछले हफ़्ते भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विवादास्पद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम, 2025 के नियमों को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया. आलोचकों का कहना है कि यह कानून पारदर्शिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नई बाधाएं पैदा करता है।

जेल में आजम खान को नहीं मिली कंबल, प्रशासन दिया ये जवाब....सेल बदलने की भी मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद कोर्ट से हिरासत में लेकर उन्हें रामपुर जेल भेज दिया गया था। अब खबर आ रही है कि आजम खान जेल बदलने की डिमांड और घर से कंबल मंगाने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि बीते दिनों फर्जी पैन कार्ड के मामले में MP -MLA कोर्ट ने आजम खान एवं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल भेजा था। दोनों को फिलहाल बी कैटेगरी सेल में रखा गया है, लेकिन आजम खान ने ए कैटेगरी सेल की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने घर से कंबल मंगाने की भी अनुमति मांगी थी, लेकिन जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए कंबल लेने से इनकार कर दिया। घर से आए लोगों को भी लौटा दिया गया।

अदालत लेगी फैसला

जेल प्रशासन ने आजम खान की दोनों मांगों ए कैटेगरी सेल और कंबल की रिपोर्ट अदालत को भेज दी है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

2 पैनकार्ड का मामला

मिली जानकारी के अनुसार, आजम के बेटे अब्दुल्ला के एक पैनकार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है. पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पैन कार्ड मामले में आजम खां भी आरोपी थे।

भजापा विधयाक ने किया था केस

गौलतलब है कि 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जो मामला MP -MLA कोर्ट में चल रहा था और आज यानी की सोमवार को फैसला आया है और दोनों को सात साल सजा सुनाई गई है।

आजम खान के परिवारव पर मुकदमें

बहरहाल, कोर्ट से सजा मिलते ही आजम खान और उनके बेटे दोनों को फिलहाल, रामपुर जेल में भेज दिया गया है। बता दें कि आजम खान और उनके परिवार पर कई मुकदमे दर्ज हैं...खुद आजम खान पर करीब 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं...उनके बड़े बेटे अदीब पर 20 से अधिक और छोटे बेटे अब्दुल्ला पर करीब 40 केस और पत्नी पर करीब 30 मामले दर्ज हैं...हालांकि कई मामलों में आजम खान बरी हो चुके हैं, जबकि कई मामलों में अभी सुनवाई जारी है और फैसले बाकी हैं।

उधर शेख हसीना को मौत की सजा, इधर अचानक भारत आ धमके बांग्लादेश के NSA रहमान, क्या मकसद?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है. शेख हसीना की मौत की सजा के बाद बांग्लादेश में फिर उथल-पुथल है. मोहम्मद यूनस के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है. लोग सड़कों पर उतर आए हैं. खुद हसीना के घर पर भी हमला हुआ है. कुल मिलाकर बांग्लादेश में हालात फिर पिछले साल जैसे हो गए हैं, जब तख्तापलट हुआ था. उधर बांग्लादेश में शेख हसीना की मौत की सजा पर बवाल है. इधर बांग्लादेश के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अचानक नई दिल्ली आ धमके हैं. दरअसल, बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) खालिलुर रहमान मंगलवार की शाम 6:30 बजे के बाद दिल्ली पहुंचे।

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, वह पहले तय कार्यक्रम से एक दिन पहले भारत आए हैं. मतलब यह है कि खालिलुर रहमान आज यानी बुधवार को भारत आने वाले थे. मगर तय शेड्यूल से एक दिन पहले वह भारत आ चुके हैं. मंगलवार की शाम को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के एक सीनियर अधिकारी ने उनका स्वागत किया. लेकिन सवाल उठ रहा है कि ढाका में शेख हसीना की सजा पर मचे बवाल के बीच एनएसए रहमान का एक दिन पहले आने का क्या मकसद है?

शेख हसीना को सजा और बवाल

दरअसल, शेख हसीना को 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर घातक बल प्रयोग के आरोप में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई. ट्रिब्यूनल ने उन्हें पांच मामलों में दोषी करार दिया, जिसमें उत्तेजक भाषण देने के लिए उम्रकैद तक की सजा शामिल है. शेख हसीना 2024 के बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद भारत में रह रही हैं. इस फैसले ने ढाका में हंगामा मचा दिया है. समर्थकों ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' बताया, जबकि विरोधी इसे न्याय की जीत मान रहे हैं. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्रिब्यूनल की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और मौत की सजा का विरोध किया. सूत्रों की मानें तो भारत ने इसे 'अवैध और अमान्य' करार दिया है।

क्यों भारत आए रहमान?

इधर, एनएसए रहमान का दौरा आधिकारिक तौर पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (सीएससी) की 7वीं एनएसए-स्तरीय बैठक के लिए है, जो 19-20 नवंबर को दिल्ली में होनी है. भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने उन्हें आमंत्रित किया था. सीएससी में भारत, मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों जैसे आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता पर चर्चा होती है. बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) खलीलुर रहमान कल यानी गुरुवार को एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे।

बांग्लादेशी एनएएस क्या करेंगे भारत में?

बुधवार को वह सदस्य देशों के ह्य और शीर्ष अधिकारियों के लिए रखे गए डिनर में भी शामिल होंगे. यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब एक दिन पहले ही बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है. अब सवाल है कि आखिर तय समय से एक दिन पहले बांग्लादेशी एनएसए के आने की वजह है क्या है? अभी तक इसका कारण पता नहीं चल पाया है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि रहमान का जल्दी आना द्विपक्षीय वार्ता का संकेत हो सकता है. माना जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना के मुद्दे पर भी शायद बातचीत हो. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं आया है।

संक्षिप्त ख़बरें

पाकिस्तान ने 50 अरब रुपए का अतिरिक्त रक्षा बजट किया मंजूर, अफगान-ईरान बॉर्डर पर फिर लगेगी बाड़

पाकिस्तान सरकार ने देश की सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने, नौसैनिक अड्डों को उन्नत करने और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की सुरक्षा बनाए रखने के वास्ते 50 अरब पाकिस्तानी रुपए (PKR) के रक्षा अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया कि यह फैसला मंगलवार को मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) की बैठक में लिया गया। अखबार के मुताबिक वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में हुई ईसीसी की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, खाद्य सुरक्षा और पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया।

खबर के मुताबिक कुल राशि में से 39 अरब पीकेआर थलसेना को तथा लगभग 11 अरब पीकेआर नौसेना को आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया, ''ईसीसी ने रक्षा प्रभाग की ओर से संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत अनुपूरक मांग को मंजूरी दे दी है, जिसमें विभिन्न अनुमोदित रक्षा सेवा परियोजनाओं के लिए 50 अरब पीकेआर अनुदान का अनुरोध किया गया था।'' ईसीसी ने विशेष सुरक्षा प्रभाग दक्षिण के लिए 19 अरब पीकेआर की मंजूरी दी, जो एक साल पहले की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।

विशेष दक्षिणी प्रभाग दक्षिणी क्षेत्रों में विदेशी वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उत्तरी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशेष सुरक्षा प्रभाग उत्तरी के लिए आठ अरब पीकेआर आवंटित किये गए हैं। मंजूर अनुपूरक रक्षा बजट में दो अरब पीकेआर की राशि अफगानिस्तान और ईरान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने के लिए आवंटित की गई है। ईसीसी ने नौसेना के दो ठिकानों के उन्नयन के लिए 11 अरब पीकेआर की मंजूरी दी। खबर के मुताबिक यह अतिरिक्त 50 अरब पीकेआर जून में सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा बजट के रूप में आवंटित 2,550 अरब पीकेआर के अतिरिक्त है।

खालिस्तानी-गैंगस्टर नेटवर्क का गहरा जाल, कोर्ट में NIA की ये सॉलिड दलील, तुरंत जज ने दी अनमोल की 11 दिन की कस्टडी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की NIA कस्टडी में भेज दिया गया है. NIA के वकील राहुल त्यागी ने बताया कि बिश्नोई पर गंभीर आरोप हैं और उसकी रिमांड से कई अहम कड़ियां सामने आ सकती हैं. इस मामले में खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर नेटवर्क का कनेक्शन भी जांच के दायरे में है, जिसे एजेंसी अब खंगालेगी. NIA का मानना है कि बिश्नोई से पूछताछ बड़े सिंडिकेट की संरचना और अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा कर सकती है।

एनआईए ने मांगी थी 15 दिन की कस्टडी

एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल बिश्नोई की भूमिका विस्तार से बताते हुए उसकी 15 दिन की कस्टडी मांगी है. एजेंसी के अनुसार वह सिंडिकेट का 19वां सदस्य है और पूरी गैंग की फंडिंग, ऑपरेशन मॉडल और नेटवर्क को समझने के लिए उसकी कस्टोडियल पूछताछ बेहद जरूरी है. एनआईए का कहना है कि बिश्नोई की पूछताछ से गैंग के और सदस्यों की पहचान हो सकती है. शाम 5 बजे के करीब अनमोल बिश्नोई

कोर्टरूम में पहुंचा, जहां वह अपने वकील से बातचीत कर रहा है. एनआईए सूत्रों के मुताबिक उसके खुलासे पूरे नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश करा सकते हैं।

बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी अनमोल

अनमोल बिश्नोई पर NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होने का आरोप है. 12 अक्टूबर 2024 की रात बांद्रा में बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि अनमोल, शुभम लोंकर और ज़ीशान मोहम्मद अख्तर को वांटेड घोषित किया गया था. मुंबई पुलिस ने इस केस में MCOCA लगाया है और अब अनमोल की भारत वापसी के बाद उसकी कस्टडी की मांग भी की जाएगी।

सलमान के घर पर भी करवाई थी फायरिंग

इसके साथ ही अनमोल बिश्नोई अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए गोलीकांड में भी वांटेड है. अप्रैल 2024 में हुई इस घटना के बाद पुलिस जांच में अनमोल की भूमिका सामने आई थी. इसके अलावा वह सिद्धू मूसेवाला हत्या में भी संदिग्ध कड़ी के रूप में सामने चुका है. इस घटना में पकड़े गए युवकों से पूछताछ के दौरान अनमोल का नाम सामने आया था. विदेश में बैठे-बैठे उसने सलमान के घर गोलियां चलवाई थी।

मूसेवाला हत्याकांड में भी आया नाम

अनमोल बिश्नोई का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक अहम कड़ी माना जाता है. जांच एजेंसियों के अनुसार, अनमोल कनाडा में बैठकर अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हमले की साजिश का हिस्सा था. कहा जाता है कि उसने शूटरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियारों की व्यवस्था और टारगेट की मूवमेंट से जुड़ी जानकारी मुहैया कराई. NIA की चार्जशीट में भी उसके डिजिटल चैट, कॉल रिकॉर्ड और विदेशी फंडिंग से जुड़े कई सुराग शामिल हैं. इसी भूमिका के चलते उसे मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा- राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड संबंधी एक मामले में सवाल उठाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अपनी मशीनरी का इस्तेमाल 'राजनीतिक लड़ाई' में क्यों कर रहा है. डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मंगलवार (18 नवंबर) को झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों और पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगने वाली सीबीआई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, 'आप अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम आपको कई बार बता चुके हैं.' मालूम हो कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट के 23 सितंबर के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीआई को राज्य विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नति में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि सीजेआई बीआर गवई की बेंच मंगलवार को सीबीआई की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई कर रही थी. इस मामले पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सीबीआई की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. वहीं, इस मामले में झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि जब भी कोई मामला आता है, सीबीआई पहले ही अदालत में पेश हो जाती है. हालांकि, सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस बात से असहमति जताई और तर्क दिया कि अपराध होने पर सीबीआई पेश होती है, लेकिन पीठ इससे सहमत नहीं नज़र आई.

ज्ञात हो कि इससे पहले जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन पीठ बाद में झारखंड विधानसभा सचिवालय और अन्य द्वारा हाईकोर्ट के 23 सितंबर, 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।

सीबीआई का कथित दुरुपयोग और एजेंसी में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या

गौरतलब है कि विपक्ष लगातार सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित 'दुरुपयोग' को लेकर सवाल उठाता रहा है. चुनाव के समय प्रतिद्वंद्वी दलों और उनके नेताओं के खिलाफ छापेमारी, तलाशी और गिरफ्तारियों को लेकर कई बार चुनाव आयोग से भी संपर्क किया गया है. हालांकि, आयेग अक्सर इस संबंध में चुप्पी साधे ही नज़र आता है. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की बीते साल आई वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 31 दिसंबर 2023 तक भ्रष्टाचार से जुड़े केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच वाले 6,900 से अधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, जिनमें से 361 मामले 20 सालों से अधिक पुराने हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भ्रष्टाचार के 658 मामले सीबीआई जांच के लिए लंबित हैं. वहीं, इनमें से 48 मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 31 दिसंबर 2023 तक की स्थिति को देखें तो सीबीआई में 1,610 खाली पद थे, जबकि इसमें स्वीकृत पदों की संख्या 7,295 थी. इनमें से 1,040 कार्यकारी रैंक के हैं. वहीं, 84 कानून अधिकारी, 53 तकनीकी अधिकारी, 388 मंत्रालयीन कर्मचारी और 45 कैंटीन कर्मचारी हैं।

एक बार फिर बदलने वाला है आपका आधार, अब न नाम होगा और न पता, कार्ड पर फोटो के साथ होगा सिर्फ क्यूआर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- आधार आज कितना जरूरी है, यह तो आप जान ही चुके होंगे. आपकी सभी वित्तीय पहुंच बिना आधार के संभव नहीं हो सकती है. जाहिर है कि इतने जरूरी डॉक्यूमेंट के गलत इस्तेमाल का खतरा भी खूब होता है. इसी खतरे को भांपते हुए आपके आधार को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने एक बार फिर इसमें बदलाव की बात कही है. आने वाला नया आधार कार्ड सिर्फ आपकी फोटो और एक क्यूआर के साथ होगा. इसमें पहले की तरह लिखे नाम, पते और आधार कार्ड के नंबर को हटा दिया जाएगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) लोगों से जुड़ी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने और ऑफलाइन सत्यापन को हतोत्साहित करने के लिए धारक की तस्वीर और क्यूआर कोड के साथ आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है. आधार पर आयोजित एक सम्मेलन में यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) भुवनेश कुमार ने कहा कि प्राधिकरण दिसंबर में एक नया नियम लाने पर विचार कर रहा है, ताकि होटल, कार्यक्रम आयोजकों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा ऑफलाइन सत्यापन को हतोत्साहित किया जा सके. साथ ही

व्यक्तियों की गोपनीयता बनाए रखते हुए आधार का उपयोग करके आयु सत्यापन प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके।

कैसा होगा नया आधार कार्ड

कुमार ने कहा, 'इस बारे में विचार किया जा रहा है कि कार्ड पर किसी और विवरण की जरूरत क्यों हो. इसमें केवल तस्वीर और क्यूआर कोड होना चाहिए. अगर हम और जानकारी छापेंगे, तो लोग वही मानेंगे और जो लोग इसका दुरुपयोग करना जानते हैं, वे करते रहेंगे.' इसका मतलब है कि अब आधार कार्ड पर सिर्फ आपकी फोटो और एक क्यूआर कोड होगा, जिसमें आपकी सभी जानकारियां गोपनीय रूप से सुरक्षित रहेंगी और इसका दुरुपयोग भी नहीं हो सकेगा।

सत्यापन में टूट रहे नियम

आधार अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी ऑफलाइन सत्यापन के लिए इकट्ठा, उपयोग या संग्रहित नहीं की जा सकती. फिर भी कई संस्थाएं आधार कार्ड की फोटोकॉपी इकट्ठा करती हैं और स्टोर भी करती हैं. ऐसे में उनके साथ धोखाधड़ी या इन आधार का गलत इस्तेमाल होने की संभावना बनी रहती है. इससे बचने के लिए ही आधार में सारी जानकारियां अब गोपनीय करने की तैयारी है, ताकि ऑफलाइन सत्यापन पर रोक लगाकर लोगों की जानकारियों के गलत इस्तेमाल को भी रोका जा सके।

आधार सत्यापन पर क्या नियम

देश में आधार का सत्यापन बिना धारक की सहमति के नहीं किया जा सकता है और कोई भी संस्था ऐसा करती है तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. यह सहमति बायोमेट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही ली जाएगी, जो धारक से ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आइरिस आदि के जरिये कराया जा सकता है. केवल UIDAI की ओर से अधिकृत संस्था और बैंक ही आधार का सत्यापन कर सकते हैं. यूजर चाहे तो अपने बायोमेट्रिक डाटा को लॉक भी कर सकता है और तब सिर्फ ओटीपी ही काम करेगा. अगर कोई आधार के डाट का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

झांसी की वीरांगना: रानी लक्ष्मीबाई का राष्ट्रप्रेम और प्रेरणादायक संघर्ष

रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उस चमकते सितारे की तरह उभरता है, जिसकी रोशनी समय बीतने के बाद भी धुंधली नहीं पड़ती। उनका जीवन केवल अतीत का एक अध्याय नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के भारत के लिए एक जीवित प्रेरणा है। यह प्रेरणा केवल युद्धभूमि की वीरता तक सीमित नहीं, बल्कि स्वाभिमान, अधिकार और न्याय के लिए डटकर खड़े होने की अदम्य इच्छा से जन्म लेती है। जब हम झांसी की रानी को याद करते हैं, तो हम एक ऐसे चरित्र को स्मरण करते हैं जिसने विपरीत परिस्थितियों को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति और संकल्प का साधन बना लिया।19वीं सदी का भारत, विशेषकर 1850 के दशक का दौर, औपनिवेशिक शासन के दमन, राजनीतिक षड्यंत्रों और सामाजिक असमानताओं से भरा हुआ था। ऐसे समय में एक युवा स्त्री का सत्ता, राजनीति और सैन्य नेतृत्व के केंद्र में आना अपने आप में एक क्रांति थी। मणिकर्णिका तांबे, जिन्हें लोग प्यार से मनु कहते थे, बचपन से ही निर्भीक थीं। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला में उनकी दक्षता उस समय की स्त्रियों के पारंपरिक दायरे से बिल्कुल अलग थी। जब परिस्थितियों ने उन्हें झांसी की रानी बनाया, तब उन्होंने केवल राजसिंहासन नहीं संभाला–उन्होंने अपने लोगों की उम्मीदों, सुरक्षा और सम्मान की बागडोर भी थाम ली। ब्रिटिश शासन की 'हड़प नीति' किसी राज्य की स्वायत्तता को छीनने वाली एक कठोर रणनीति थी। झांसी को इस नीति का निशाना बनाया गया तो रानी के सामने दो रास्ते थे–समर्पण या संघर्ष। उन्होंने संघर्ष को चुना, और वही निर्णय था जिसने उन्हें सामान्य राजसत्ता से उठाकर इतिहास में अमर नायिका बना दिया। 'मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी'–यह वाक्य केवल प्रतिरोध की घोषणा नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक अन्याय के खिलाफ एक सशक्त प्रतिवाद था जो अंग्रेज़ी शासन भारतीय रियासतों पर थोप रहा था। 1857 का विद्रोह भारतीय जनमानस की दबी हुई पीड़ा का विस्फोट था। इस आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई ने जिस नेतृत्व का परिचय दिया, उसने साबित किया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल पुरुषों की नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी सेना खड़ी की जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। झलकारी बाई जैसी योद्धा सिर्फ सैनिक नहीं थीं, बल्कि इस संग्राम की प्रतिध्वनि थीं, जो दिखाती थीं कि स्वाधीनता एक सामूहिक संकल्प है। झांसी पर जब ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज़ ने हमला किया, तब जिस प्रकार रानी ने किले की रक्षा की, वह किसी महाकाव्य से कम नहीं था। तीन सप्ताह तक निरंतर युद्ध, सीमित संसाधन और भारी विरोधी सेना–इन सबके बावजूद रानी ने न तो किले को छोड़ा और न ही मनोबल को टूटने दिया। अंततः जब किला टूटने की कगार पर था, तब वह दुश्मन को चकमा देकर अपने पुत्र को पीठ पर बाँधे युद्धभूमि से बाहर निकलीं। इस दृश्य में मातृत्व और शौर्य का ऐसा संगम है जिसकी मिसाल इतिहास में दुर्लभ है। कालपी और फिर ग्वालियर में उन्होंने जो रणनीतिक युद्ध लड़े, वे यह दर्शाते हैं कि रानी केवल साहसी योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल सैन्य नेतृत्वकर्ता भी थीं। ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर उन्होंने यह सिद्ध किया कि उनके संघर्ष की व्यापकता केवल झांसी तक सीमित नहीं थी; वह संपूर्ण राष्ट्र के स्वाभिमान का युद्ध था। कोटा की सराय में हुए अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी, परन्तु हार नहीं मानी। यही कारण है कि ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज़ ने भी स्वीकार किया कि विद्रोहियों में रानी सबसे खतरनाक और सबसे प्रभावशाली थीं। आज, लगभग डेढ़ सदी बाद, रानी लक्ष्मीबाई की विरासत केवल इतिहास पुस्तकों में दर्ज कुछ पंक्तियों तक सीमित नहीं है। वह भारतीय स्त्री शक्ति का एक जीवंत प्रतीक हैं–जो बताता है कि अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता की लड़ाई किसी भी काल में न्यायोचित है। वह यह भी स्मरण कराती हैं कि सत्ता या अधिकार केवल पुरुषों की बपौती नहीं, बल्कि क्षमता और संकल्प रखने वाले किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। रानी की कहानी उन लाखों भारतीय महिलाओं के संघर्ष का भी रूपक है जो असमानता, दमन और सामाजिक बेड़ियों के खिलाफ लड़ती रही हैं। उनकी विरासत स्वतंत्र भारत की उस मूल भावना से जुड़ती है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है। रानी लक्ष्मीबाई की शौर्यगाथा हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि इतिहास अपने नायकों को केवल उनकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उनके साहस, नैतिकता और उस समय के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता से आंकता है। यदि 1857 के संग्राम में वह सिर्फ झांसी की रक्षा करतीं, तो वह केवल एक रानी बनकर रह जातीं। परंतु उन्होंने राष्ट्र की चेतना को जगाने का कार्य किया–और यही उन्हें चिरस्थायी बनाता है। आज जब हम उन्हें स्मरण करते हैं, तो यह केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक प्रतिबद्धता भी है कि हम स्वतंत्रता, न्याय और समानता के उन मूल्यों को जिंदा रखें, जिनके लिए उन्होंने युद्धभूमि में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें यह संदेश देता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में सत्य और न्याय का दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उनकी विरासत हमें न केवल प्रेरित करती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि स्वाधीनता किसी एक युग की उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता और संघर्ष का परिणाम है।

महेन्द्र तिवारी

संपादकीय

आतंक की खतरनाक साजिश से निबटने के लिए सतर्कता जरूरी

देश को एक बार फिर देश में ही छिपे गद्दारों के जरिए विदेशी मदद से आतंकवाद की आग में झोंकने की बड़ी साजिश की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ होते ही डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह भारत के खिलाफ ट्रेड टेरिफ का हथियार इस्तेमाल किया लेकिन भारत नहीं झुका इसके बाद ट्रंप की सनक बढ़ गई और उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ रिश्ते बढाकर दबे पांव भारत में अस्थिरता के बीज बोने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। आपको पता है कि 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में 26 हिन्दू पर्यटकों की हत्या और 10 नवम्बर, 2025 को दिल्ली में लाल किले के निकट आत्मघाती कार बम विस्फोट द्वारा 15 निर्दोष लोगों की हत्या का कनैक्शन 'जैश-ए-मोहम्मद' के साथ निकला है। इस बीच 15 नवम्बर को 'श्रीनगर' के 'नौगाम' पुलिस थाने में एक विस्फोट में 10 लोगों की मौत व 32 अन्य घायल हो गए। इनमें 27 पुलिस कर्मी हैं। भारत में सफेद कोट माड्यूल बना कर जिस तरह एक समुदाय विशेष के दर्जनों उच्च शिक्षित डॉक्टरों के जरिए आतंक फैलाने की बड़ी साजिश की गई जिस का समय रहते भंडाफोड़ हो गया। इसके पीछे भी विदेशी मदद का हाथ है। हाल ही में अमेरिका के प्रयास से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच समझोता करा कर भारत में ने सिरे से कश्मीर को मुद्दा बना कर वहां के शिक्षित लोगों की भावनाओं को भड़का कर भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची जा रहीं हैं। तमाम आतंकी घटनाओं के बाद भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है जिसके तहत पिछले दिनों में की गई गिरफ्तारियों तथा बरामदगियों से मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। आपको बता दें 13 नवम्बर को कश्मीर के 'सोपोर' से 2 हाईब्रिड आतंकवादियों 'शब्बीर अहमद नाजर' तथा 'शब्बीर अहमद मीर' को गिरफ्तार करके उनसे एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 20 जिंदा राऊंड तथा 2 हथगोले बरामद किए गए। 13 नवम्बर को ही उत्तर प्रदेश के 'हापुड़' और 'फिरोजाबाद' जिलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे 46 किलो 'हाईड्रोक्लोरिक एसिड' और 2.5 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए गए। 13 नवम्बर को ही पश्चिम बंगाल के 'बीरभूम' जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे जिलेटिन की 20,000 छड़ें बरामद की गई। अतः क्या आतंकवादी 'दिल्ली' की तरह 'बंगाल' को दहलाने की कोशिश कर रहे थे ? 14 नवम्बर को 'लाल किला विस्फोट' में प्रयुक्त कार के आत्मघाती ड्राइवर 'डा. उमर नबी' के पुलवामा जिले में स्थित मकान को सुरक्षा बलों ने आई.ई.डी. से विस्फोट करके उड़ा दिया।14 नवम्बर को ही अधिकारियों ने 'नूह' से 2 और मैडीकल छात्रों 'मुस्तकीम' तथा 'मोहम्मद' को हिरासत में लिया।15 नवम्बर को ही 'दिल्ली बम विस्फोट' के सिलसिले में 'पठानकोट' और 'नूह' से 2 डाक्टरों 'रईस अहमद भट्ट' तथा 'रेहान' को हिरासत में लिया गया।15 नवम्बर को ही 'अहमदाबाद' (गुजरात) में 'गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते' ने एक आतंकवादी गिरोह के लिए हथियारों की तस्करी करने में शामिल 'गुरप्रीत सिंह' उर्फ 'गोपी बिल्ला' को गिरफ्तार किया 15 नवम्बर को ही 'फिरोजपुर' में भारत-पाक सीमा पर बी.एस.एफ. ने खेतों में 2 ड्रोन व पाकिस्तान से भेजी गई 549 ग्राम हैरोइन का पैकट बरामद किया। 16 नवम्बर को 'अमृतसर कमिश्नरेट' पुलिस ने पाक आधारित हथियार और नार्को नैटवर्क का पर्दाफाश करके 1.01 किलो हैरोइन और 6 आधुनिक पिस्तौलों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 16 नवम्बर को ही सी. आई.ए. ने सफेदपोश आतंकवादी माड्यूल मामले में जम्मू-कश्मीर के 'अनंतनाग' जिले में एक महिला डाक्टर के घर पर छापेमारी की और वहां से एक मोबाइल जब्त कर अपने साथ ले गई16 नवम्बर को ही 'राष्ट्रीय जांच ब्यूरो' ने 'लाल किला' कार बम विस्फोट के हमलावर 'डा. उमर उन नबी' के साथी 'आमिर राशिद अली' तथा अगले दिन 17 नवम्बर को एक अन्य साजिशकर्ता 'जसीर बिलाल वानी' को गिरफ्तार किया। और अब 17 नवम्बर को सुरक्षा एजेंसियों को घटनास्थल पर एक जूता मिला है जिसमें 'अमोनियम नाईट्रेट' तथा जरा सी गर्मी से फटने वाले अत्यंत खतरनाक विस्फोटक 'टी.ए.टी.पी. के अंश मिले हैं। इसे देखते हुए इस धमाके में 'जूता बम' के इस्तेमाल का भी शक व्यक्त किया जा रहा है। इसे पाकिस्तान का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा

कि अपने देश की जनता की बदहाली दूर करने के लिए प्रयास करने की बजाय इसके शासक और सेना आतंकवादियों को पाल रही है और उनकी सहायता से भारत में तबाही मचा रही है। हालत यह है कि गरीबी के कारण पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए हैं जबकि 2 लाख बच्चे तो कभी स्कूल गए ही नहीं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की 'शहबाज शरीफ' सरकार द्वारा फील्ड मार्शल 'असीम मुनीर' के दबाव में सुप्रीमकोर्ट की शक्तियों को कम करने वाले 'विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन' के विरुद्ध 16 नवम्बर को वकीलों ने हड़ताल की। हम मानते हैं आतंकवादियों द्वारा पहलगाम व दिल्ली आदि में मारे गए निर्दोषों की जान कभी वापस नहीं आ सकती है लेकिन इन वारदातों के बाद सरकार तथा सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत से आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करके अनेक लोगों का जीवन बचा लिया है।ये साजिश खत्म होने वाली नही है अभी भी खतरा टला नहीं है,देव असुर संग्राम थमने वाला नहीं है अतः आतंकवादियों तथा उनके मददगारों के विरुद्ध सफाई के अभियान को तब तक और तेजी से जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि आतंकवादियों का समूल सफाया नहीं हो जाता वहीं देश के भीतर छिपे गद्दारों रेडिकलाइज चरम पंथी लोगों पर भी नजर रखनी होगी खासकर उन कट्टरपंथी मजहबी व्यक्तियों और संस्थानों पर जो अलफलाह यूनिवर्सिटी की तरह चरमपंथी षडयंत्र का अड्डा बन सकते हैं।भारत की खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक तेज तर्रार तकनीकी युक्त प्रशिक्षण और अत्याधुनिक सुविधाओं व साधनों से समृद्ध करने की जरूरत है ताकि आतंक के बदलते चेहरे की पहचान और समय रहते खात्मा किया जाए।

मनोज कुमार अग्रवाल

शौचालय बनाना सिर्फ एक बुनियादी सुविधा न होकर, महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समानता की लड़ाई है

विश्व शौचालय दिवस (World Toilet Day) सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि शौचालय तक पहुँच और स्वच्छता सिर्फ बुनियादी मानवाधिकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, स्वास्थ्य सुरक्षा और गरिमा का मामला है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन ने इस दिशा में अहम कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, विशेष रूप से महिलाओं का मामला। महिलाओं की स्थिति और शौच के अभाव में चुनौतियाँ बड़ी मुश्किल राहे थी।भारत में पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण, महिलाओं अक्सर खुले में शौच के लिए मजबूर होती थीं। यह सिर्फ स्वास्थ्य-खतरे का मामला नहीं था, बल्कि उनकी सुरक्षा, गरिमा और आत्मसम्मान से जुड़ा सवाल था।सुरक्षा और असमर्थता खुले में शौच करने का मतलब होता था दूर-दूर जाना, अक्सर अंधेरे में या असुरक्षित स्थानों पर। महिलाओं के लिए यह खतरा दोगुना था । उन्हें यौन उत्पीड़न, जान-बचाव की परेशानी और शारीरिक असुविधा का सामना करना पड़ता था। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं और किशोर लड़कियों के लिए यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी होती थी। स्वास्थ्य और स्वच्छताखुले में शौच के कारण कीचड़, कीड़े, बैक्टीरिया और मैल घुला पानी आसपास फैलता था, जिससे डायरिया, गंदे पानी से संक्रामक रोगों का जोखिम बढ़ता था। इस तरह की स्थितियाँ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भारी असर डालती थीं। गरिमा और सामाजिक दबाव महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के लिए इज्जतघर बहुत मायने रखते हैं। बिना शौचालय के, उन्हें न केवल शारीरिक असुविधा बल्कि सामाजिक शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती थी। कई जगहों पर महिलाएं इससे जुड़ी सामाजिक बंदिशों और शर्मिंदगी के कारण अपनी ज़रूरतों को छिपाती थीं या जोखिम भरा विकल्प चुनती थीं।सरकार की भूमिका और शौचालय निर्माण की प्रगति स्वच्छ भारत मिशन का दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके दो हिस्से थे। ग्रामीण (SBM-G) और शहरी (SBM-)। इसका प्रमुख लक्ष्य था ओपन डेफेक्शन फ्री (ODF) भारत बनाना।सरकार ने अपनी नीति में यह माना कि सिर्फ शौचालय बनाना ही पर्याप्त नहीं है उन्हें बनाना तो पहला कदम है, लेकिन उसके बाद उपयोग, रख-रखाव, व्यवहार परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन बेहद ज़रूरी हैं।निर्मित शौचालयों की संख्या करोड़ो में है।स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने बड़े पैमाने पर निर्माण किया है। सितंबर 2024 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11.66 करोड़ घर-घर शौचालय बनाए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में, SBM-Urban के अंतर्गत 63.63 लाख (लगभग 6.36 करोड़) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा, शहरी हिस्से में लगभग 6.36 लाख (636,000) सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर 2.41 लाख से अधिक सामुदायिक सैनिटरी (सार्वजनिक) परिसर तैयार किए गए हैं। लगभग 5.87 लाख गाँवों को ओडीएफ ,+ स्टेटस मिला है, जहाँ सिर्फ खुले में शौच खत्म करने के बाद ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तक किया जा रहा है। इस तरह की उपलब्धियाँ इस मिशन की गंभीरता और व्यापकता को दर्शाती हैं। लोगों की सोच शौचालय के प्रति जन दृष्टिकोण और जनता की सोच इस मिशन के बारे में मिश्रित है। कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण हैं, तो कुछ आलोचनाएँ भी।लोगो के सकारात्मक दृष्टिकोण है कि इसे मोदी सरकार की प्रमुख सफलता के रूप में देखते हैं ।उन्होंने दस वर्ष के अंदर लाखों-करोड़ों शौचालय बनवाए, जिससे पहले खुले में शौच करना सामान्य था और अब बहुत से गाँव और शहर ओडीएफ घोषित हुए हैं।महिलाओं और बच्चों की गरिमा में सुधार हुआ है। इज्जतघर का विचार सिर्फ भौतिक सुविधा नहीं, एक सामाजिक परिवर्तन भी है।स्वास्थ्य पर असर भी सकारात्मक दिखता है ।बच्चों में डायरिया जैसी बीमारियों में कमी, और स्वच्छता से जुड़ी जागरूकता बढ़ी है। .नकारात्मक और सतर्क दृष्टिकोण केवल लोगो का ही नही है। विपक्ष भी हमलावर है और देश का विकास उनको पच नही रहा है।कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद लोगो को मुलभुत सुविधा देने के लिए कभी सकारात्मक रुख नही अपनाया।जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। कुछ विशेषज्ञ और समाजशास्त्री कहते हैं कि सिर्फ निर्माण ही काफी नहीं है। IMPRI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई घरों में शौचालय बने होने के बावजूद, हर जगह उनका उपयोग नहीं हो रहा है। रख-रखाव की बड़ी समस्या है। कई शौचालयों में साफ-सफाई, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन नहीं हो पाता।व्यवहार परिवर्तन का काम अधूरा है। कुछ जगहों पर लोग फिर भी खुले में जाना पसंद करते हैं, या उपयोग न करने की आदत बन गई है क्योंकि उनकी निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी या सुविधाएँ सीमित थीं। मोदी सरकार को लोग कैसे देखते हैं ।मोदी सरकार को स्वच्छता को हिंदुस्तान की प्राथमिकता बनाने के लिए बहुत सम्मान मिला है। यह मिशन न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में पेश किया गया है।सरकार के बजट और संसाधन आवंटन को एक गंभीर सरकारी प्रतिबद्धता माना गया है । कई लोगों के नज़र में यह दिखाता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ घोषणाएँ नहीं की, बल्कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई की।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस मिशन को पहचान मिली है, जिससे भारत की स्वच्छता छवि में सुधार हुआ है। कुछ आलोचक कहते हैं कि सरकार ने शुरुआत में पर्याप्त बजट नहीं दिया था, या आवंटन और रिलीज़ के बीच देरी रही। भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। निर्माण ठेकेदार, दलाल, स्थानीय मिस्त्रीगण और सरकारी एजेंसियाँ लाभ में शामिल हो सकती हैं।उपयोग और रख-रखाव के बाद की विस्तार योजनाओं (जैसे ODF Plus) में जनता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी कुछ जगहों पर सुस्त है।भ्रष्टाचार, बिचौलिये और कमी समस्या के पहलूआज भी विधमान है।भ्रष्टाचार इस मिशन की चुनौतियों में एक बड़ी बाधा रही है। बिचौलियों और दलालों की भूमिका में ग्रामीणों के मजबूरी का फायदा उठाया गया है।कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि शौचालय निर्माण में स्थानीय दलाल और मिडिलमैन शामिल होते हैं। वे लाभ कमाने के लिए निम्न-मानक निर्माण सामग्री उपयोग करते हैं। ठेकेदारों और मिस्त्रीगण कभी-कभी गुणवत्ता नियंत्रण की अनदेखी करते हैं, जिससे टॉयलेट की दीवारें, टैंक या सीटें खराब बनती हैं।दावा किया गया है कि लाभार्थियों को मिलने वाली राशि (वित्तीय सहायता) पूरी तरह गायब नहीं होती, बल्कि कुछ हिस्सा दलालों या ठेकेदारों के पास चला जाता है।जिसमे पंचायत के कार्मिक से लेकर उच्च अधिकारी और सरपंच शामिल रहते थे। यह वित्तीय हस्तक्षेप लोगों तक सीधा नहीं पहुँचने का कारण बनता है।इस वजह से, कुछ परिवारों के हाथ में आठ-दस हजार जैसा हिस्सा आता है, जबकि शौचालय निर्माण में खर्च उससे कहीं अधिक हो सकता है। यह लाभ विभाजन और पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।दोष सिर्फ केंद्र सरकार को देना उचित नहीं है। राज्य सरकारें, पंचायत स्तर के अधिकारी, स्थानीय ठेकेदार और मिस्त्रीगण भी जिम्मेदार हैं। निगरानी तंत्र में कमज़ोरी रही है । तीसरे पक्ष की जांच, सतत निगरानी और जवाबदेही प्रणाली मजबूत नहीं रही है। लाभार्थियों की भागीदारी सीमित रही है।सामाजिक जांच और समुदाय-नेतृत्व को और बढ़ाना चाहिए।विपक्षी दल और आलोचक इस मिशन को पूरी तरह नकार नहीं करते, लेकिन उनकी चिंताएँ स्पष्ट हैं। विपक्ष का मानना है कि बहुत से शौचालय निर्माण संख्या का खेल बन गए हैं।सिर्फ संख्या दिखाने के लिए निर्माण किया गया, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान कम गया। कुछ जगहों पर दो सीट वाला एक ही टॉयलेट जैसा विचित्र निर्माण मुद्दे सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा मामला सामने आया है। पर्याप्त राशि नहीं जारी की गई विपक्ष यह तर्क देता है कि केंद्र ने शुरू में पर्याप्त बजट आवंटन नहीं किया या राज्य और पंचायती स्तर पर फंड रिलीज़ में देरी की। ये देरी यानी कम राशि योजना को समय पर और प्रभावी रूप से लागू करने में बाधा बनती हैं। रख-रखाव और व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान न देना।कई विपक्षी नेताओं की राय है कि मोदी सरकार सिर्फ निर्माण को महत्व देती है, लेकिन निर्माण के बाद उपयोग, सफाई, मरम्मत और समुदाय की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही। वे कहते हैं कि स्वच्छता योजना का असली परिणाम तभी दिखेगा जब शौचालय नियमित रूप से उपयोग किए जाएँ और उनके रख-रखाव का सही प्रबंधन हो। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमीदेखी गई। विपक्ष उन मामलों को उजागर करता है जहाँ निर्माण दर में अनियमितताएँ और लाभार्थियों तक सीधे पैसों के न पहुँचने के आरोप हैं। वे चेतावनी देते हैं कि अगर निगरानी मजबूत नहीं हुई, तो स्वच्छता मिशन लंबे समय में टिकाऊ नहीं रह सकेगा। आगे का विजन और समाधान भी सरकार का सकारात्मक है। भविष्य में स्वच्छता और शौचालयों के क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं:सरकार को . ODF Plus और व्यवहार परिवर्तन लाना चाहिए। भारत को सिर्फ ओपन डेफेक्शन फ्री लक्ष्य से आगे बढ़कर ODF Plus की ओर जाना होगा, जहाँ न सिर्फ खुले में शौच खत्म हो, बल्कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी सुनिश्चित हो। व्यवहार परिवर्तन के लिए सामाजिक जागरूकता अभियानों को मजबूत किया जाना चाहिए।पंचायत स्तर पर महिलाएँ और युवा नागर समिति नेतृत्व लें। रख-रखाव और प्रणालीगत निगरानीजरूरी है। बनाए गए शौचालयों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता कॉल सेंटर, ऐप-आधारित शिकायत प्रणाली और स्थानीय स्वच्छता समितियाँ होनी चाहिए। वित्तीय सहायता सिर्फ निर्माण तक सीमित न हो

।मरम्मत, सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी बजट निर्धारित करना चाहिए। निर्माण में शामिल ठेकेदारों और मिस्त्रियों के लिए स्पष्ट तकनीकी मानक और गुणवत्ता नियंत्रण नियम लागू किए जाने चाहिए। लाभार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामाजिक ऑडिट पंचायत-स्तर की समीक्षा समितियाँ और तीसरी पक्ष की निगरानी आवश्यक है। भ्रष्टाचार और बिचौलियों को नियंत्रित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र तेज़ और प्रभावी होना चाहिए। पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए विशेष शौचालय की संख्या बढ़ानी चाहिए, खासकर शहरी झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों में, ताकि महिलाओं को निजी, सुरक्षित और स्वच्छ सुविधा मिले। हर शौचालय योजना में महिला प्रतिनिधि को निर्माण और रख-रखाव समितियों में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उनकी ज़रूरतें और अनुभव सीधे नीति निर्माण में आएँ। स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों और महिलाओं के लिए स्वच्छता शिक्षा और सुरक्षित शौचालय सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए। स्क्रूटनी पैनल और लोक शिकायत तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए ताकि लाभार्थियों की शिकायतों का निपटारा हो सके। पंचायत स्तर पर 'स्वच्छता जगृति दल' बनाए जाएँ, जो स्थानीय लोगों की निगरानी करें और भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ लोक अभियानों का नेतृत्व करें। डिजिटल ट्रेसबिलिटी जैसे GPS-टैगिंग, फोटो सबमिशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि निर्माण की वास्तविकता और गुणवत्ता की पुष्टि हो सके। विश्व शौचालय दिवस पर हमें यह समझना चाहिए कि शौचालय बनाना सिर्फ एक बुनियादी सुविधा न होकर, महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समानता की लड़ाई है। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से अभूतपूर्व प्रगति की है करोड़ों शौचालय बनाए, लाखों गाँव हृष्ठस्न घोषित किए गए, और सार्वजनिक बहस को आगे बढ़ाया गया। लेकिन चुनौतियाँ अभी खत्म नहीं हुई हैं: भ्रष्टाचार, बिचौलियों की जड़ें, गुणवत्ता की गिरावट, उपयोग और रख-रखाव की अनदेखी, और विशेष रूप से महिलाओं की ज़रूरतों पर पर्याप्त ध्यान न देना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें नज़दीक से संबोधित करना होगा। लोक, विपक्ष, सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से महिलाएँ केवल शौचालय का अस्तित्व न पाएं, बल्कि सुरक्षित, स्वच्छ, उपयोगी और सम्मानजनक शौचालय का अनुभव कर सकें। इस रूपांतरण को स्थायी और टिकाऊ बनाने के लिए ODF Plus के विजन, पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।देश मे शौचालय निर्माण सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि गिनी जा रही है।

कांतिलाल मांडोत

बिहार में भाजपा की भारी जीत से राजनीतिक संतुलन

केंद्र-राज्य समीकरण और आने वाले चुनावों पर प्रभाव

भारत की राजनीति में बिहार हमेशा से एक निर्णायक और रणनीतिक राज्य रहा है। जातीय संरचना, सामाजिक समीकरण, विकास का विमर्श और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका।इन सबके कारण बिहार के परिणाम अक्सर पूरे देश के राजनीतिक मानस को प्रभावित करते रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 243 सीटों वाले सदन में भाजपा का इस तरह से भारी बहुमत लेकर आना केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीतिक दिशा और राष्ट्रीय वातावरण का संकेत भी है। बिहार में नीतीश को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है।इस जीत ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, के प्रति जनविश्वास को पुनः प्रमाणित किया है। साथ ही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की मजबूती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र और राज्य के बीच तालमेल विकास की रफ्तार तय करता है। यह विजय केवल राजनीतिक नहीं, बल्किप्रशासनिक और जन-कल्याणकारी नीतियों की स्वीकृति के रूप में भी देखी जा रही है।भाजपा की क्यों है यह इतनी महत्वपूर्ण?बिहार में भाजपा की भारी जीत के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनके पूरे राज्य की राजनीति का नया मार्ग निर्धारित किया है।जन-आधार और कैडर की मजबूती, भाजपा पिछले एक दशक से बिहार में अपनी संगठनात्मक जड़ें मजबूत कर रही थी। बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुख मॉडल और सतत जनसंवाद ने पार्टी को गांव-गांव तक मजबूत नेटवर्क दिया। यह चुनाव उस आधार का प्रत्यक्ष परिणाम था। विकास और सुरक्षा का मुद्दा जोर से चलाया गया।बिहार में वर्षो से कानून-व्यवस्था, रोजगार, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हमेशा चर्चा में रहे हैं। भाजपा ने कठिन परिस्थितियों में भी केंद्र से बिहार को विशेष सहायता दी थी।सड़क परियोजनाएँ, रेल कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप और उद्योग सम्बर्धन। इन सबने जनता के बीच विश्वास निर्माण किया कि स्थिर सरकार के साथ विकास तेजी से संभव है।मोदी फैक्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी कई राज्यों में निर्णायक कारक है। बिहार में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने चुनाव को मोदी के नेतृत्व पर विश्वास के रूप में देखा। मोदी का संदेश विकसित बिहार-विकसित भारत–सीधे जनता की आकांक्षाओं से जुड़ा मुद्दा चर्चित रहा।नीतीश कुमार और भाजपा की जोड़ी साख स्थिरता का समीकरण है। नीतीश कुमार भारत के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। शासन, प्रशासन और सुशासन के उनके मॉडल को देश ने कई बार सराहा है। भाजपा-जदयू गठबंधन को जनता ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसमें अनुभव , नवोन्मेष का संतुलन था।नीतीश कुमार की प्रशासनिक साख औरमोदी सरकार की नीतिगत विश्वसनीयतादोनों साथ आए।इस गठबंधन की जीत यह संकेत देती है कि बिहार की जनता स्थिरता चाहती है। विकास कार्य रुकें नहीं, योजनाओं का प्रवाह बना रहे और केंद्र-राज्य संबंध सुचारु रहें।यही जनइच्छा इस भारी जनादेश के रूप में सामने आई है।केंद्र और राज्य पर इसके प्रभाव इस परिदृश्य का असर न केवल बिहार पर पड़ेगा बल्कि केंद्र सरकार के निर्णयों, राष्ट्रीय राजनीति और भविष्य की योजनाओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव दिखेगा।केंद्र का राजनीतिक स्वास्थ्य और मजबूती भाजपा की इस भारी जीत ने यह साबित किया है कि जनता अब भी केंद्र सरकार की नीतियों पर चल रही है।इंफ्रास्ट्रक्चर विकास,डिजिटल भारत, सामाजिक सुरक्षा, गरीब कल्याण योजनाओं, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थितिसे संतुष्ट है। यह जीत राजनीतिक विपक्ष को भी नया संदेश देती है कि जनता राष्ट्रहित और विकास के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है। राज्य सरकार की कार्यक्षमता में वृद्धि देखी जा रही है।केंद्र के साथ बेहतर तालमेल मिलने अधूरी परियोजनाएँ तेजी से पूरी होंगी,फंडिंग में बाधाएँ कम होंगी, बड़ी योजनाओं पर तेजी आएगी। नीतीश-मोदी तालमेल से बिहार की अपेक्षाएँ और बढ़ गई हैं। अब अधूरे कार्य होंगे पूर्ण और बिहार अब जरूर बदलेगा। जनादेश ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है। 'विकास को गति दीजिए, रुकी हुई योजनाएँ पूर्ण कीजिए। सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे गंगा ब्रिज, पटना मेट्रो, बिहार एक्सप्रेसवे, दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाएँ अब और तेज गति से आगे बढ़ेंगी।उद्योग और निवेशभाजपा सरकार की डबल इंजन नीति से औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, रोजगार सृजन, स्टार्टअप पारिस्थिति तंत्र, कौशल विकास में अभूतपूर्व प्रगति होने की संभावना है।शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र की योजनाओंऔर आईआईटी, आईआईएम, एम्स विस्तार, नई स्वास्थ्य सुविधाओं को गति मिलेगी। किसान और ग्रामीण विकास पीएम-किसान, सिंचाई, कृषि बाजार, जैविक खेती और ग्रामीण सड़क योजना जैसे कदमों से ग्रामीण बिहार को लाभ होगा।बिहार के परिणाम केवल एक राज्य तक सीमित प्रभाव नहीं रखते। यह राजनीतिक संदेश है कि जनता अब भी विकास आधारित राजनीति चाहती है।गठबंधन टिके रहने चाहिए,विपक्ष को अपनी रणनीति बदलनी होगी। यह जीत उत्तर भारत के कई राज्यों में भाजपा के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है। बिहार का यह परिणाम केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करने वाला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा लंबे समय से सशक्त चुनौती देने का प्रयास कर रही है। बिहार की इस जीत से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ेगी,बंगाल के हिंदू-वोट बैंक पर असर पड़ेगा,केंद्र की विश्वसनीयता बढ़ेगी,ममता बनर्जी के खिलाफ विपक्ष को संयोजन मिलेगा। सीमा क्षेत्र, बंगाल-बिहार भाषाई व सांस्कृतिक कनेक्टिविटी के कारण यह परिणाम बंगाल में भी माहौल बनाता है। बिहार की जीत के बाद भाजपा को पश्चिम बंगाल में रणनीति तेज करने का लाभ मिलेगा।बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करती है, क्योंकि दोनों राज्यों में सामाजिक संरचना में समानताएँ हैं। NDA की स्थिति और मजबूत होगी।विपक्ष का मनोबल कमजोर होगा।बिहार के राजनीतिक वातावरण का झारखंड पर हमेशा असर रहा है।वहाँ भी भाजपा के लिए माहौल सुधरेगा,संगठन को बढ़वा मिलेगा।बिहार के परिणाम से पूर्वी भारत में भाजपा की स्थिति और मजबूत होगी, जिससे इन राज्यों में भी चुनावी रणनीति को मजबूती मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के लिए राह आसान क्यों होगी? बिहार में भाजपा की भारी जीत से पश्चिम बंगाल में पार्टी की स्थिति मजबूत होने के कई कारण हैं।तेज चुनावी जीत हमेशा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। यह लहर पड़ोसी राज्यों तक भी जाती है। बिहार-बंगाल की सीमाएँ मिलती हैं, व्यापारिक संबंध और जन-आवागमन घनिष्ठ है।

ऐसे में एक राज्य में बनी राजनीतिक लहर दूसरे में भी असर डालती है। बिहार के परिणाम के बाद बंगाल के मतदाता भी केंद्र सरकार के विकास मॉडल की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं। बिहार में विपक्ष की हार यह संकेत देती है कि अगर विपक्ष संयुक्त न हुआ और मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं किया, तो बंगाल में भी भाजपा को चुनौती देना कठिन है।मोदी और नीतीश की साख क्यों बढ़ी है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा,गरीब वर्ग के लिए योजना-प्रधान नीतियाँ, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर मजबूत छवि मोदी की साख को लगातार मजबूत करती हैं। बिहार के परिणाम इस साख का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।सुशासन,प्रशासनिक अनुशासन, सामाजिक कार्यक्रम, महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएँ ने नीतीश कुमार को एक भरोसेमंद नेता बनाया है। दोनों नेताओं की विश्वसनीयता ने मिलकर इस चुनाव को निर्णायक बनाया।बिहार में भाजपा की भारी जीत केवल चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में हो रहे बड़े परिवर्तन का संकेत है।जनता स्थिरता चाहती है, विकास चाहती है,केंद्र-राज्य एकता को प्राथमिकता देती है, गठबंधन सरकार पर भरोसा जताती है,राष्ट्रीय नेतृत्व की विश्वसनीयता बढ़ रही है।यह जीत न केवल बिहार की राजनीति को नए द्वार देगी, बल्कि आने वाले चुनावों विशेषकर पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए स्थितियाँ अनुकूल बनाएगी।भारतीय राजनीति अब उस दौर में प्रवेश कर रही है जहाँ जनादेश विकास, सुशासन और विश्वसनीय नेतृत्व पर आधारित है। बिहार का यह परिणाम इसी दिशा में एक मजबूत कदम है।

कांतिलाल मांडोत

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

सपा प्रत्याशी अफजाल कौशर की अध्यक्षता में जाम को लेकर उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला को सौपा ज्ञापन

बिसवां सीतापुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सपा प्रत्याशी अफजाल कौशर की अगुवाई में कस्बे में लगने वाले जाम को लेकर ज्ञापन उप जिला अधिकारी शिखा शुक्ला को सौपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है। कि गन्ने की गाड़ियों के कारण अक्सर नगर में जाम लग रहा है। जिससे आम जनमानस परेशान हो रहा है साथ ही व्यापार भी प्रभावित है ।इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि गन्ने की गाड़ियों में रेडियम प्लेट नहीं लगी है। जिसके चलते अंधेरे में सामने से आने वाली गाड़ियां नजर नहीं आती। जिसके चलते अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार होते है। कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र से कस्बे को आने वालों मे दुर्घटनाएं होने का भय बना रहता है। उन्होंने सभी गन्ने की गाड़ियों में रेडियम प्लेट लगाने की भी बात मांग पत्र मे कही है। ज्ञापन देने वालों में श्याम सिंह यादव, नूर नेता, अनिल मिश्रा, सावेज अंसारी, लुकमान अली, अयूब खान, शिव प्रताप वर्मा, धर्मेंद्र सिंह सहित कई सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

किराए पर लिये तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां हड़पने का आरोप

भट्टे में लगाने के लिए दतिया ले गये थे, एफआईआर दर्ज

ललितपुर। तालबेहट के ग्राम रजावन निवासी छक्कीलाल पुत्र सु मान ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। बताया कि बीती 15 जून 2025 को शाम करीब 4 बजे उसके घर से सोनालिका ट्रैक्टर नंण् यूण्पीण् 94 एण्केण् 5450 व मनोज कुमार पुत्र सालिगराम का ट्रैक्टर आयशर नंण् यूण्पी०94 एणएफण् 6652ए ग्राम चन्द्रापुर के मजरा कशा निवासी रामकुंवर पत्नी छत्रपाल सिंह का ट्रैक्टर स्वराज नंण् यूण्पीण् 94 जेड 5056 को मध्य प्रदेश के जिला दतिया में भट्टे पर किराए पर लगाने के लिए गांव का ही राजेश प्रजापति पुत्र हन्ना ने बात करके मध्य प्रदेश के जिला दतिया के भाण्डेरी फाटक ग्राम बंदर की हवेली हाऊस नंण् 164 ;कद्ध निवासी राजेन्द्र व शंकर प्रजापति पुत्रगण लालाराम और दतिया की आरामशीन दरगाह के मुहल्ला ठण्डी सड़क निवासी राहुल कुशवाहा पुत्र सुरेश के साथ तीनों ट्रैक्टर एवं ट्रॉलियों को साथ ले गये। आरोप है कि अभी तक उक्त ट्रैक्टर.ट्रालियां अभी तक वापस नहीं किये। पीड़ित का आरोप है कि उक्त लोगों ने तीनों ट्रैक्टरों व ट्रॉलियों को बेईमानी की नीयत से रख लिया है और वापस नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर उक्त लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 ;2द्ध के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

प्रेमी जोड़े ने बाल्हेश्वर मंदिर में रचाई शादी, चार साल पुराने प्रेम को मिला अंजाम

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र के ऐहार गांव स्थित सुप्रसिद्ध बाल्हेश्वर मंदिर में मंगलवार को एक प्रेमी जोड़े ने परिवार की सहमति से विधि-विधान के साथ विवाह संपन्न किया। नवविवाहित दंपती को परिजनों व ग्रामीणों ने आशीर्वाद देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।नकफुलहा गांव के निवासी बृजेश और ऐहार के पूरे अजबी मजरे की रामपती पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध में थे। प्रारंभ में दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। विवाह को लेकर कई बार पंचायत भी बैठी, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद परिजन युवक-युवती को बाल्हेश्वर मंदिर ले गए। जहां वैदिक मंत्रोच्चार और हिंदू रीति- रिवाजों के बीच उनका विवाह सम्पन्न कराया गया। वर-वधू ने एक- दूसरे को वरमाला पहनाई और जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। विवाह समारोह में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश फौजी सहित रामसजीवन, राजबहादुर, राजू, सुरेंद्र, रामलोटन स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने नवदंपती को उपहार और आशीर्वाद देकर उनके वैवाहिक जीवन की मंगलकामनाएँ दीं।

बेख़ौफ़ चोरों के हौंसले बुलंद, ई-रिक्शा से चार बैटरी चोरी

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर वलौली गांव स्थित एक ढाबा के निकट सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने दरवाजे खड़े ई-रिक्शा की बैटरी खोल कर ले गए। पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। मोहल्ला निवासी आनंद कुमार ने बताया कि रोज की तरह उसका ई-रिक्शा दरवाजे पर चार्जिंग के लिए लगाया गया था। बीती रात अज्ञात चोर ई-रिक्शा की चारों बैटरी खोल ले गए। इससे उसका करीब 45 हजार रुपए का नुकसान हो गया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है।

समाजसेवी पत्रकार पर जानलेवा हमला: साजिश का दावा, मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग तेज

● ....पीड़ित ने प्रभावशाली कारोबारी पर साजिश रचने का आरोप लगाया, डीसीपी दक्षिणी ने एसीपी मोहनलालगंज को जांच सौंपी; विभिन्न संगठनों ने उठाई कड़ी कार्रवाई की मांग।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज। संवाददाता राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में समाजसेवी व पत्रकार मुकेश द्विवेदी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित पत्रकार ने मंगलवार को डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल से मुलाकात कर इस हमले के पीछे गहरी साजिश होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल असल साजिशकर्ता अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और हमलावरों को किसी प्रभावशाली कारोबारी के इशारे पर भेजा गया था। शिकायत पर डीसीपी दक्षिणी ने पूरे प्रकरण की जांच एसीपी मोहनलालगंज को सौंपते हुए तथ्यों की गहराई से जांच के निर्देश दिए हैं।

पत्रकार मुकेश द्विवेदी के अनुसार 13 नवंबर को वह अपनी कार सर्विस सेंटर से लेकर लौट रहे थे, तभी तीन कारों में सवार हमलावर उनका लगातार पीछा कर रहे थे। बीसीसी हाइट्स के पास जैसे ही उन्होंने गाड़ी मोड़ी, हमलावरों ने उनकी कार को दोनों ओर से घेरकर टक्कर मारने का प्रयास किया। स्थिति भांपते हुए वह अपनी सूझबूझ से गाड़ी को मोड़कर अंदर स्थित एक प्लॉट तक पहुंच गए, लेकिन हमलावर भी वहां तक पहुंच गए थे। पीड़ित के शोर मचाने पर स्थानीय लोग दौड़े, जिसके बाद हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों अभिषेक तिवारी, विनीत तिवारी, चंदन भट्ट, हरिनाम, राहुल रावत और अमित मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा कि हमले के पीछे किसी बड़े कारोबारी की भूमिका हो सकती है, जिसने द्वेषवश यह साजिश रची। उन्होंने कहा कि उनकी जान पूरी तरह खतरे में थी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की सक्रियता और उनकी सतर्कता से वह बच सके। उन्होंने पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सौंपे हैं और दावा किया है कि यदि उन बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की जाए तो पूरे हमले की साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा और असली मास्टरमाइंड सामने आ जाएगा।

इधर मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने भी चिंता जताई है। प्रेस क्लब निगोहा, करनी सेना के दुर्गेश सिंह दीपू, किसान नेता अनमोल तिवारी तथा पत्रकार एसोसिएशन मोहनलालगंज के महामंत्री अखिलेश द्विवेदी ने संयुक्त रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की गहनता से जांच कर साजिशकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में भय का माहौल खत्म हो और पीड़ित को न्याय मिल सके।

स्टेशन तिराहे पर शराबियों का आतंक, यात्रियों से अभद्रता, आवागमन में बाधा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

तालबेहट। नगर के व्यस्तम स्टेशन रोड तिराहे पर स्थित कलारियों के चलते शराबियों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि दिनभर आनेदृजाने वाले यात्रियों को इनकी हरकतों से परेशानी झेलनी पड़ती है। शराब के नशे में धुत लोग राहगीरों से अभद्रता करते हैं और वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे न सिर्फ यात्री बल्कि स्थानीय लोग भी भारी असुविधा महसूस कर रहे हैं। यह तिराहा न सिर्फ रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वालों का प्रमुख मार्ग हैए बल्कि आसपास के दर्जनों ग्रामों का संपर्क मार्ग भी इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ शराबियों की बढ़ती उपस्थिति सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बन गई है।

कई बार यात्रियों और वाहन चालकों के साथ विवाद की परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही तिराहा शराबियों के कब्जे में चला जाता हैए जिससे महिलाएं व छात्र.छात्राएँ सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तिराहे पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और कलारियों पर नियंत्रण के लिए स त कार्रवाई की जाए। यात्रियों और आमजन का कहना है कि यदि जल्द ही प्रभावी कदम न उठाए गए तो किसी भी दिन बड़ी घटना हो सकती है। स्थानीय नागरिकों ने सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने की अपील की है।

अपर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली का किया निरीक्षण

लालगंज रायबरेली। अपर पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान अभिलेखों और मालखाने की जांचकर उचित रखरखाव के निर्देश दिए। लंबित शिकायतों और उनके निस्तारण की समीक्षा की।उन्होंने महिला सुरक्षा साइबर अपराध और रात्रि गस्त को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एएसपी संजीव कुमार सिन्हा दोपहर करीब 2 बजे कोतवाली पहुंचे। जहां उन्होंने सबसे पहले आगंतुक रजिस्टर माल खाना महिला हेल्प डेस्क मिशन शक्ति केंद्र, महिला पुलिस परामर्श केंद्र कंप्यूटर सलाह कक्षा का निरीक्षण किया। दस्त भेजो कि जांच कर उनके उचित रखरखाव के निर्देश दिए। कोतवाली परिषद में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए नियमित गस्त, निगरानी टीम और ग्राम स्तर तक संपर्क सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहां की प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों की शिकायतें निस्तारित की जाए। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह इंस्पेक्टर क्राइम अनिल कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस अफसर मौजूद रहे।

बिल्ली मारकुंडी खदान हादसे में सीआईएसएफ की त्वरित कार्रवाई, राहत कार्य में निभाई अहम भूमिका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ओबरा/सोनभद्र, 18 नवंबर 2025 - दिनांक 15.11.2025 को बिल्ली मारकुंडी स्थित श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स खदान में हुई हृदय विदारक दुर्घटना के बाद, ओबरा तापीय विद्युत परियोजना स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सदस्यों ने राहत एवं बचाव कार्य में अपनी अहम और त्वरित भूमिका निभाकर एक बार फिर कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। यह दुखद घटना कंप्रेसर कार्य के दौरान हुई, जब पत्थर के दरकने से खदान के ऊपरी हिस्से से भारी मात्रा में मलबा गिर गया, जिसके नीचे कई कामगार दब गए। स्थानीय प्रशासन से सूचना मिलते ही, सीआईएसएफ के कमांडेंट सतीश कुमार सिंह ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने अपनी अग्नि शाखा के 1 फायर टेंडर, अधिकृत क्रू मेंबर्स और सुरक्षा बल के सदस्यों के साथ तुरंत घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। सीआईएसएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सबसे पहले राहत एवं बचाव कार्य की शुरुआत की। उनकी तत्परता के मु य बिंदु इस प्रकार रहे। घोर अंधेरे वाली खदान में राहत एवं बचाव कार्य के लिए पर्याप्त प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जो रात के समय ऑपरेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी।राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों के घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत भी, सीआईएसएफ के बल सदस्य उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार सक्रिय रहे। राहत एवं बचाव कार्य में लगी सभी एजेंसियों के लिए समुचित भोजन पैकेजिंग और जरूरत के सभी आवश्यक सामान तुरंत मुहैया कराए गए। हादसे में पीड़ित परिवारों को लगातार सांत्वना दिलाते हुए, सीआईएसएफ ने अपनी संवेदनशील छवि को भी मजबूत किया।सीआईएसएफ द्वारा की गई इस सराहनीय कार्रवाई और तत्परता ने एक बार फिर उनके आदर्श वाक्य सुरक्षा एवं

संरक्षण को आत्मसात करते हुए यह साबित कर दिया है कि सीआईएसएफ के बल सदस्य सदैव कर्तव्यनिष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ न केवल भारत के उद्यम एवं धरोहर की सुरक्षा करते हैं, बल्कि देश के आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रहरी भी बने रहेंगे। आपदा के इस कठिन समय में सीआईएसएफ की यह त्वरित और निर्णायक भूमिका निःसंदेह सराहनीय है और यह दर्शाती है कि सुरक्षा बल अपनी तैनाती क्षेत्र से बाहर भी जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

मुकदमा में सुलह न करने से महिला से छेड़छाड़ का आरोप

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने सात लोगों पर मारपीट व छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासिनी महिला ने बताया कि गत 22 अक्टूबर की शाम को एक पुराने विवाद में सुलह की दबिश बनाने को लेकर हंसनापुर गांव निवासी मुन्ना उर्फ विनोद कुमार सोनी, गुड्डू सोनी, पूरे बदई गांव निवासी इंद्रेश यादव व टिल्लू, शीतलाबख्श खेड़ा मजरे मधुकरपुर गांव निवासी धर्मेंद्र व बैसन का पुरवा गांव निवासी दीपू उसके घर घुस आए। गाली गलौज करते हुए उसे पकड़ कर गिरा दिया और उसके साथ अभद्रता की। शोरगुल मचाने पर आरोपी धमकाते हुए फरार हो गए। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

राज्य विद्युत परियोजना जूनियर इंजीनियर्स संगठन (रा वि प जू इं) शाखा अनपरा का वार्षिक निर्वाचन संपन्न

● अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह और सचिव आवेश कुमार निर्विरोध निर्वाचित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अनपरा सोनभद्र– राज्य विद्युत परियोजना जूनियर इंजीनियर्स संगठन (रा वि प जू इं) की अनपरा शाखा का वार्षिक निर्वाचन आज, 16 नवंबर 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह निर्वाचन संगठन के संविधान के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी इंजीनियर नवीन कुमार सिंह की देखरेख में अवर अभियंता मनोरंजन कैदे में आयोजित किया गया। इस वर्ष के निर्वाचन में, ई. धर्मेंद्र कुमार सिंह को अध्यक्ष पद के लिए और ई. आवेश कुमार को सचिव पद के लिए निर्विरोध चुना गया। यह निर्विरोध निर्वाचन संगठन के सदस्यों के बीच मजबूत सहमति और एकता को दर्शाता है। अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त, शेष पदों पर भी पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सूची इस प्रकार है।वरिष्ठ उपाध्यक्ष ई. धीरेन्द्र कुमार चौबे, उपाध्यक्ष ई. मनोज कुमार पाल, संगठन सचिव ई. विष्णु देव झा, वित्त सचिव ई. आशीष कुमार, प्रचार सचिव ई. अजहरुद्दीन, लेखा निरीक्षक ई. अमित कुमार मौर्य संगठन के वार्षिक निर्वाचन के अवसर पर सदस्यों की भारी उपस्थिति दर्ज की गई, जो संगठन के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करती है। प्रमुख रूप से ज्ञानेंद्र पटेल, आनंद कुमार, अशोक साहू, धर्मेंद्र रामकरण, ध्रुव कुमार, चंद्रमणि, अमित कुमार, अजित, मोहित यादव, कृपा शंकर शुक्ला सहित अन्य सदस्यों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी की। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने इस अवसर पर संगठन की एकजुटता बनाए रखने और सभी सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। उनका यह संकल्प संगठन के भविष्य के एजेंडे को स्पष्ट करता है, जिसमें सदस्यों के कल्याण और संगठन की मजबूती पर मु य ध्यान दिया जाएगा।

भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार रस्तोगी पर लाठियां से हमला अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल

बिसवां सीतापुर। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार रस्तोगी पर अज्ञात हमलावर ने लाठियों से हमला कर दिया। जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गये। कस्बे के मोहल्ला पुरवारी टोला निवासी प्रतिदिन की भाति सुबह पांच बजे कस्बे के शीतला देवी मंदिर से होकर कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थिति पत्थर शिवाला धाम आ रहे थे कि सियाल मेडिकल स्टोर के पास अज्ञात हमलावर ने लाठी से हमला कर दिया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गये, डायल एक सौ बारह पुलिस को फोन पर सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने सीएचसी बिसवां पहुंचाया जहा डाक्टरों ने उन्हे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया।जहा उनका उपचार चल रहा है। कस्बे की मनसा राम चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह ने बताया घटना जानकारी मे नही है।तहरीर मिलेगी तो कार्यवाही की जाएगी।

कार्यवाही की मांग को लेकर सड़क जाम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। मलिहाबाद में प्रेम प्रसंग से जुड़े एक मामले में 17 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए किशोरी के परिवार पर आरोप लगाया है। मंगलवार को शव घर पहुंचने पर आक्रोशित परिजनों ने लखनऊ-हरदोई राजमार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर परिजनों को समझाया। पाठकगंज महमूदनगर निवासी रामगोपाल ने बताया कि उनका बेटा विकास कुमार एक माल इलाके की लड़की से प्रेम-प्रसंग में था। रविवार को विकास किशोरी को कहीं भगा ले गया था। इससे नाराज होकर लड़की के परिजन सोमवार सुबह उनके घर पहुंचे और पुलिस केस करने की धमकी दी थी। इसके बाद विकास के परिजन उसकी तलाश में जुट गए। सोमवार शाम लगभग साढ़े चार बजे उन्हें सूचना मिली कि विकास का शव घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर मुजासा रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर

पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही परिजनों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने महमूदनगर ढाल स्थित लखनऊ-हरदोई राजमार्ग पर शव रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे, जिससे करीब एक घंटे तक दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और सड़क से जाम हटाया गया। मलिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

रीता वर्मा प्रजापति बनीं समाजवादी महिला सभा की प्रदेश महासचिव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भदोही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश तथा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की संस्तुति पर समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव ने भदोही की पूर्व जिलाध्यक्ष रीता वर्मा प्रजापति को प्रदेश महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। नव-नियुक्त प्रदेश महासचिव रीता वर्मा प्रजापति के समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए फूलमालाओं से लाद दिया। सभी ने उन्हें बधाई देते हुए पार्टी की नीतियों को मजबूती से आगे बढ़ाने और महिलाओं के हक व अधिकारों की लड़ाई को और सशक्त करने के लिए शुभकामनाएं दीं।पार्टीजनों का मानना है कि रीता वर्मा प्रजापति के अनुभव व संगठन

कौशल से महिला मोर्चा को और मजबूती मिलेगी।

स्वागत कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, विधायक जाहिद बेग, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, पूर्व विधायक मधुबाला पासी, प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी, पूर्व प्रत्याशी अंजनी सरोज, पूर्व जिला पंचायतअध्यक्ष श्यामला सरोज, जिलामहासचिव हृदय नारायण प्रजापति, वि.स. अध्यक्ष भदोही संतोष यादव, वि.स. अध्यक्ष ज्ञानपुर लालचंद बिद, वि.स. अध्यक्ष औराई केशनारायण प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष कल्लन यादव, कमलेश यादव, सलाउद्दीन अंसारी, गामा प्रसाद यादव, प्रदीप वियोगी, पवन विश्वकर्मा, कमलाशंकर महतो, पिछड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष काशीनाथ पाल, लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष दिलीप भीम कनौजिया, मजदूर सभा जिलाध्यक्ष गुलाब पाल, संतोष यादव, बैजनाथ यादव, राम सिंह, कमलेश बिंद, जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र पप्पू सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इलाहाबाद हाई कोर्ट से मोदीनगर बम ब्लास्ट में दोषसिद्ध इलियास बरी, हाई कोर्ट ने कहा- पुलिस के समक्ष कबूलनामा अस्वीकार्य

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। वर्ष 1996 में मोदीनगर-गाजियाबाद में चलती बस में हुए विस्फोट की घटना को लेकर उम्र कैद काट रहे मोह मद इलियास को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए भारी मन से बरी कर दिया है कि पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। अपने 51 पेज के निर्णय में खंडपीठ ने कहा- अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा और पुलिस द्वारा दर्ज इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रतिबंध के मद्देनजर अस्वीकार्य है। इलियास की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा, अपीलकर्ता के खिलाफ कानूनी रूप से स्वीकार्य कोई साक्ष्य नहीं बचा है। इसलिए वह 'भारी मन से' बरी करने का आदेश पारित कर रही है। घटना में 18 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, रुड़की डिपो की बस 27 अप्रैल 1996 की दोपहर 3:55 बजे लगभग 53 यात्रियों को लेकर दिल्ली से रवाना हुई। मोहननगर में 14 और यात्री इसमें सवार थे। शाम करीब पांच बजे, बस के अगले हिस्से में शक्तिशाली विस्फोट हुआ और 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि लगभग 48 यात्री घायल हुए। पोस्टमार्टम में शवों में धातु के टुकड़े पाए गए। डॉक्टरों ने बताया कि मौतें बम विस्फोट के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के चलते कारण

हुई। फोरेंसिक जांच में ड्राइवर की सीट के नीचे कार्बन मिला आरडीएक्स रखे जाने की पुष्टि हुई थी।

विस्फोट रिमोट स्विच के ज़रिए किया गया था। अभियोजन का आरोप था हमले को पाकिस्तानी नागरिक और हरकत-उल-अंसार के कथित जिला कमांडर अब्दुल मतीन उर्फ इकबाल ने मोह मद इलियास (अपीलार्थी) और तस्लीम के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मूल रूप से मुज फरपुर निवासी लेकिन लुधियाना में रहने वाले इलियास को ज मू-कश्मीर के आतंकवादियों ने भड़काया था। वर्ष 2013 में निचली अदालत ने सह अभियुक्त तस्लीम को बरी कर दिया, लेकिन इलियास और अब्दुल मतीन को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास के साथ-साथ कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। तस्लीम को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार ने कोई अपील दायर नहीं की। हाई कोर्ट के समक्ष मु य मुद्दा इलियास के इकबालिया बयान की स्वीकार्यता था। पुलिस का दावा था कि जून 1997 में लुधियाना में गिर तारी के बाद उसने पिता और भाई की मौजूदगी में बम लगाने की बात कबूल की थी। बयान सीबीसीआईडी के सेक्टर अधिकारी, विवेचनाधिकारी ने ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्ड किया था। हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन ने कुल 34 गवाहों को परीक्षित कराया था। यात्रियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना को साबित कर दिया, लेकिन कोई भी यह नहीं पहचान सका कि विस्फोटक किसने लगाया था? दरअसल बस के आईएसबीटी दिल्ली से रवाना होने से पहले बम रखा गया था, जिससे पहचान असंभव हो गई। खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत, पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया इकबालिया बयान स्वीकार्य है। खंडपीठ ने कहा, विस्फोट अप्रैल 1996 में हुआ था, जब टाडा लागू नहीं था और इस प्रकार टाडा में प्रदत्त विशेष अपवाद (जो पुलिस के इकबालिया बयानों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देता था), मामले में लागू नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस टेप रिकॉर्डर में कथित तौर पर बयान दर्ज किया गया था, उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ

● श्री राम जानकी विवाह, कन्या विवाह, यज्ञ हवन के होंगे कार्यक्रम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

तालबेहट। साहू समाज के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। यात्रा के नगर में प्रवेश करते ही नगरवासियों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत और बंदन किया। मंगलवार की दोपहर श्री राम मंदिर से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। पीतांबर वस्त्रों में सजी महिलाएं मंगलगान करती हुई शोभायात्रा में सि मलित रहींए वहीं अश्वरथ पर विराजमान आचार्य सौरभ कृष्ण शास्त्री आकर्षण का केंद्र बने रहे। मु य यजमान के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहारए अंजू परिहारए पूजा अनिल साहू सहित महिलाएं पवित्र श्रीमद् भागवत का कलश सिर पर रखकर चल रही थीं। कलश यात्रा नगर भ्रमण करती हुई मानसरोवर स्थित हजारिया महादेव तट पर पहुंचीए जहां वैदिक विधि से पवित्र जल कलश में भरकर पुनः कथा स्थल पर लाया गया। आयोजन की जानकारी देते हुए साहू समाज के अध्यक्ष अरविंद साहू ने बताया कि 18 नवंबर से 25 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान श्री रामदृजानकी विवाहए कन्या विवाहए हवनदृयज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। कलश यात्रा में साहू समाज ललितपुर, बबीना, बिजौली, प्राणपुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। आयोजन में पूर्व अध्यक्ष रामसेवक साहू, अध्यक्ष अरविंद साहू, उपाध्यक्ष जितेंद्र साहू, महामंत्री केशव साहू, कोषाध्यक्ष संतोष साहू, मंत्री अभिषेक साहू, ऑडिटर कुलदीप साहू, परमानंद साहू, संजय साहू, राजकुमार राजू साहू, विपुल साहू, अनिल साहू, सी.एल. साहू, पार्षद पी.डी. साहू, राजेंद्र साहू, ककदारी महेंद्र साहू, संजय साहू समेत साहू समाज के अन्य लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम बनी यह भव्य कलश यात्रा नगर में चर्चा का केंद्र बनी रही।

मुकदमा में सुलह न करने से महिला से छेड़छाड़ का आरोप

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने सात लोगों पर मारपीट व छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासिनी महिला ने बताया कि गत 22 अक्टूबर की शाम को एक पुराने विवाद में सुलह की दबिश बनाने को लेकर हंसनापुर गांव निवासी मुन्ना उर्फ विनोद कुमार सोनी, गुड्डू सोनी, पूरे बदई गांव निवासी इंद्रेश यादव व टिल्लू, शीतलाबख्श खेड़ा मजरे मधुकरपुर गांव निवासी धर्मेंद्र व बैसन का पुरवा गांव निवासी दीपू उसके घर घुस आए। गाली गलौज करते हुए उसे पकड़ कर गिरा दिया और उसके साथ अभद्रता की। शोरगुल मचाने पर आरोपी धमकाते हुए फरार हो गए। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

संक्षिप्त खबरें

घर में घुसकर ग्राम प्रधान को दी धमकी,चार नामजद

हमीरपुर- बिंवार थाना क्षेत्र के ग्राम कल्ला के ग्राम प्रधान शिवशरण पुत्र काशीराम ने थाने में तहरीर देकर बताया सोमवार सुबह जब वह गांव की गौशाला की देखरेख करने पहुंचा तो देखा कि, गांव को रोहित पुत्र आनंद सिंह गौशाला में टहल रहा था। ग्राम प्रधान ने बताया कि जब उससे घूमने की वजह पूछी तो गाली गलौज करने लगा। ग्राम प्रधान ने बताया कि उसके बाद दिन मे रोहित, जगदेव, आनंद सिंह और राजकुमार लाठी डण्डा लेकर उसके घर आ गए और गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने लगे।ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने चारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर शांति भंग में चालान कर दिया है। इस सम्बन्ध में थाना प्रभारी नंदलाल प्रजापति ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट का मामला है। मुकदमा दर्ज कर शांति भंग की कार्यवाही की गई है।

श्याम सेवादार मंडल नोएडा रजि. ने मनाया छठा श्री श्याम वार्षिक महोत्सव

नोएडा। श्री श्याम सेवादार मंडल नोएडा रजि. ने धूमधाम से छठा श्री श्याम वार्षिक महोत्सव नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 मे मनाया। जिसमे हजारों की संख्या में श्याम भक्त मजूद रहे। भजन गायक शीतल पाण्डेय, शिवम रावल एवं भजन गायिका अनुष्का ने बाबा खाटू श्याम के गीतों से पूरा पंडाल भक्तिमय कर दिया। आयोजक मंडल के प्रधान श्याम सेवक एवं अध्यक्ष विजय भारद्वाज ने बताया की श्री श्याम सेवादार मंडल नोएडा रजि. के द्वारा, पूरी टीम की मेहनत व सहयोग से छठा श्री श्याम वार्षिक महोत्सव धूमधाम से और भक्ति में माहौल में भंडारे के साथ आयोजित हुआ। 15 नवंबर को इस्कॉन मंदिर से स्टेडियम तक भव्य निशान यात्रा भी निकली गई। उन्होंने बताया की संस्था 7 साल पुरानी है और हर चौथे शनिवार को मासिक संकीर्तन करते हैं। पंडाल में उपस्थित सभी श्याम भक्तों को राम मेहर भारद्वाज, मांगेराम, महेश गुप्ता,आलोक यादव व संजय गर्ग ने धन्यवाद दिया।

राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर छात्र ने की आत्महत्या, शिक्षक से परेशान होने की बात आ रही सामने

छात्र ने मेट्रो स्टेशन पर की आत्महत्या।

मानसिक तनाव के कारण उठाया कदम।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच।

नई दिल्ली। राजधानी के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को एक छात्र ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। सूत्रों के मुताबिक, मृतक छात्र हाल ही में मानसिक तनाव से गुजर रहा था। प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि उसे एक शिक्षक की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण वह गंभीर तनाव में था। उसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया है। घटना की सूचना मिलते ही मेट्रो पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस छात्र का मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त कर चुकी है और जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक सभी एंगल पर जांच चल रही है। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि छात्र के मानसिक हालात और संभव कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सके।

आजमगढ़ में पशुशाला में घुस कर गोकशी करने वाले दो अपराधी गिरफ्तार

आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र की गोरथानी गांव में आठ नवंबर 2025 को पशुशाला (बरदौर) में घुस कर गोकशी करने वाले दो अपराधियों को पुलिस ने मंडोही-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान इरफान निवासी कौड़ही थाना बसखारी जिला अंबेडकर नगर और शहजादे आलम उर्फ चांद निवासी मोहल्ला अब्दुल कलाम नगर, अतरौलिया के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि वे अपने साथियो आरिफ, अखलाक, शमीम व करीम (सभी अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं) के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से गोकशी की घटना को अंजाम देते थे। आठ नवंबर को सभी पशुशाला का ताला तोड़ अंदर घुसे थे। यहां बंधी दो गोवंशों का वध कर मांस लेकर कार से फरार हो गए थे। उक्त मांस को बचने के बाद मिले राशि को आपस में बांट लिया था। पुलिस ने बदमाशों के पास से घटना में प्रयुक्त दो चापड़,10,500 नकद बरामद किया है। इरफान पर आजमगढ़ के विभिन्न थानों में 13 गोकशी सहित अन्य आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं शहजादे आलम पर दो मामले दर्ज हैं। पुलिस शेष अपराधियों के गिरफ्तारी को दबिश दे रही है।

फर्जी बिल लगाकर मालामाल हो रहे सचिव सरपंच करकटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
दिनेश चौधरी की रिपोर्ट

शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत करकटी में भ्रष्टाचार चरम पर हैं। जहाँ एक ओर सरकार हर व्यक्ति को हर सम्भव योजना के साथ साथ व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने का संकल्प लिया हैं। वही पंचायत सचिव के द्वारा सभी बिलों को छोटे छोटे अमाउंट में पंचायत दर्पण सहित अन्य पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। जिससे यह साफ हो रहा कि भ्रष्टाचार किस कदर सचिव सरपंच के द्वारा मचा रखा हैं। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए लाखों रुपए मुहैया करा रही है। जिससे ग्रामीण स्तर पर उपयोगी व सभी कार्य गुडवत्ता पूर्व हो सके। जिसमें ग्रामीणों को सुविधा मुहैया और जरूरते पूरी की जा सकें। जिसके तहत पंचायत स्तर पर शासन द्वारा चलाए गए कई योजनाएं जो ग्रामीण हित के लिए कराई जाती है, पर इस कालाबाजारी के दौर पर और मिलावट खोरी के इस दौर में हर कोई सिर्फ अपने कमिशन से मतलब रखता है। उसे निर्माण कार्य से कोई भी मतलब नहीं रहता। फिर चाहे वह किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य क्यों ना हो, कारण यह भी हैं कि अधिकारी जमीनी स्तर पर मौका मुआयना करने नहीं जाते। जिससे कि निर्माण एजेंसी और अधिकारियों की साठ-गाठ से निर्माण धीन कार्य भी अधूरा और ढहने की कगार पर हैं।

फर्जी बिलों का कारखाना है पंचायत करकटी

ग्राम पंचायतों में राजीव जायसवाल की फर्जी बिलों का जमावड़ा लगा हुआ हैं। आपको बता दे कि हाल ही लगे दो बिल ये दर्शाता हैं कि ग्राम पंचायत के बाहर 16 ट्रैक्टर मुरुम भाड़ा सहित जिसकी कीमत 15104 रुपये का बिल 16/09/25 को लगी हैं। वही दूसरी ओर 19/08/25 को रोड़ा 4000 रुपये और ट्रैक्टर भाड़ा 4000 रुपये की लागत से बिल लगाया गया हैं। लेकिंजो सच्चाई दिखती हैं उसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। आपको बता दे ग्राम पंचायत के बाहर देखकर कोई यह नहीं कर सकता हैं कि दो टाली से ज्यादा मुरुम गिरा हो। पर पंचायत सरपंच सचिव की जुगाड़ इतना कि जिले में कोई ऐसा अधिकारी भी की ग्राम पंचायत करकटी का बिल रोक सके चाहे फर्जी हो या गलत ऐ जय वीरू की जोड़ी ग्राम पंचायत में इस कदर चर्चित है कि इनकी मनमर्जी के बिना कोई काम नहीं होता।

फर्जी बिल लगाकर लूट रहे हैं ग्राम पंचायत करकटी को सरपंच सचिव की जोड़ी बनी है नं 1

हम दोनों की जोड़ी को कोई कुछ नहीं कर सकता है शासन प्रशासन को मैं अपनी जेब में रखता हूं हमारी सरकार है इस लिए सरकार के रहते मनमौजी करूंगा यहां हम दोनों का राज चलता है और हमेशा चलेगा यह बड़े दबंगई से दोनों का कहना मेरी मर्जी, इस संबंध में जानकारी मांगे गए तो फोन नहीं उठा, जिला कलेक्टर डॉ केदार सिंह शहडोल।

संकुल शिक्षक बैठक में विद्यालयों को निपुण बनाने पर हुई चर्चा

हमीरपुरः- महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर के निर्देशन में मंगलवार के दिन इंगोहटा न्याय पंचायत के विद्यालयों के शिक्षकों की संकुल शिक्षक बैठक प्राथमिक विद्यालय बिल्हडी विकास खंड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर में आयोजित की गयी। बैठक में एकेडमिक रिसोर्स परसन अकबर अली ने शिक्षक शिक्षिकाओं को निपुण प्लस, विद्यालय एप, बच्चों के आकलन, शिक्षक संदर्शिका प्रयोग, टीएलएम, परख सर्वेक्षण, निपुण लक्ष्य, दक्षताएं एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।एआरपी अभिषेक शुक्ला ने गणित टीएल एम, आकलन व एनडीएमसी को बताया। बैठक में विभिन्न विषयांतर्गत शिक्षण सामग्री को लक्ष्मी देवी, रीना राठोर, रिचा, प्रीति, किशोर कुमार, कुसुमा, नौशाद खां, बीनू पुरोषोत्तम, गुरमीत कौर, संध्या व राजीव कुमार निगम ने प्रदर्शित कर समझाया। संचालन रणजीत सिंह प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया। न्याय पंचायत इंगोहटा सुमेरपुर के समस्त नामित शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगा दिखा ट्रैक्टर ट्रॉली पर भर रहे सवारियां

● **यातायात पुलिस को किसी बडे हादसे का इंतजार**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा के दौरान होने वाले हादसों से पुलिस और यातायात पुलिस सबक नहीं ले रही है जिसके चलते एक बार फिर बडे हादसे की आहट सुनाई देने लगी है।

ज़िले में इन दिनों गांव-गांव में मेलों का दौर चल रहा है। लेकिन मेला देखने की उत्सुकता लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सवार होकर सफर कर रहे हैं।

सरकार द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवारी ढोने पर सख्त रोक लगाए जाने के बावजूद, मौदहा क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर पर ऐसी कई तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जहां मेले में जाने वाले लोग ट्रैक्टरों में बैठे दिखाई दे रहे हैं। यह वही मार्ग हैं जिन पर कई हादसे हुए हैं और लगातार हो रहे हैं सवाल यह है कि क्या ट्रैफिक पुलिस को यह ट्रैक्टर सवारियां भरकर दौड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर पुलिस किसी बड़े हादसे के इंतज़ार में है?

यातायात नियमों के मुताबिक, ट्रैक्टर केवल कृषि कार्यों के लिए मान्य हैं – लेकिन हमीरपुर में इन दिनों इनका इस्तेमाल खुलेआम सार्वजनिक सवारी ढोने में किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि किसी अनहोनी से पहले ही सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।बताते चलें कि बीते सप्ताह जिला मुख्यालय के शीतलपुर के पास ट्रैक्टर ट्राली पलटने से डेढ दर्जन लोग घायल हुए थे जबकि मौदहा कोतवाली क्षेत्र के सिजवाही निवासी एक बच्चे का मुण्डन कराने गए थे और ट्रैक्टर ट्राली पलटने से दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे वहीं बीते साल भगत बाबा का मेला देखने जाते समय कपसा रोड पर ट्रैक्टर ट्राली पलटने से दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे , जिम्मेदार एक बार फिर किसी बडे हादसे के इंतजार में हैं।

सिलापथार में जुबीन गर्ग का 53 वां जन्मदिन पालन, जिला भाजपा की तरफ़ से रक्तदान शिविर का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

धेमाजी असम। असम के दिवंगत हार्टथ्रोब जानेमाने कलाकार जुबीन गर्ग का 53वां जन्मदिन आज राज्य के विभिन्न प्रांत के साथ सिलापथार के विभिन्न क्षेत्रों में पालन किया गया। भैरबपुर आंचलिक बंगाली युवा छात्र फेडरेशन ऑफिस परिसर में असम जातीयताबादी युवा परिषद और कृषक मुक्ति संग्राम समिति के धेमाजी जिला समिति ने भैरवपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय लोगों के सहयोग से जुबिन गर्ग की प्रतिच्छवि पर पुष्पांजलि अर्पित कर नाहर पेड़ के पौधा लगाकर जन्म दिवस पालन किया।

इस कार्यकम में धेमाजी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीटूपन नियोग और साहित्यकार कस्तोरी चुटिया ने भाग लिया और जुबीन गर्ग पर बात लम्बे टिप्पणी दिया। अनुष्ठान से जुबिन गर्ग की मृत्यु के विचार पक्रिया जल्द समाप्त कर न्याय दिलाने की मांग की। दूसरी और दोनी पोलो कंपल्स सिलापथार में धेमाजी जिला बीजेपी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया।

शिविर में भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस फ्रेंच की जवानों ने भी रक्तदान किया। अनुष्ठान में विधायक भुवन पेगू, लायन्स क्लब सिलापथार के कार्यकर्ताओं, सिलापथार मंडल भाजपा के अध्यक्ष गंगा पेगू, युवा मार्च के कार्यकर्ताओं ने शिविर में भाग बढ़चढकर भाग लिया।

मिर्जापुर में सड़क हादसे में दो मजदूरों की मौत

मिर्जापुर जिले के पड़री थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह मोटरसाइकिल सवार दो मजदूरों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पड़री थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि कपसौर इलाके में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक दिहाड़ी-मजदूरी के लिए घर से निकले थे। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के शादी बनकट निवासी इंज़माम (25) और इस्राइल (22) के रूप में हुई है। थाना प्रभारी के अनुसार, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

अमृतदीप महोत्सव में भव्य शोभा यात्रा निकाल स्वामी ब्रम्हानंद की प्रतिमा का हुआ अनावरण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुरः- जिलापंचायत अध्यक्ष जयंती सन्तराम राजपूत के पिता स्व0अर्जुन सिंह व माता जी स्व0 ब्रम्हारानी की याद में जनपद के उनके पैतृक गांव करही, सरीला में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अमृत दीप महोत्सव का आयोजन व बुन्देलखण्ड में शिक्षा की अलख जगाने वाले परम पूज्य त्याग पुरुष स्वामी ब्रम्हानंद जी की शोभायात्रा और उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया।वही महोत्सव में एक दिवसीय दंगल का भी आयोजन किया गया।महोत्सव में पूर्वाह्न सुबह 9 बजे से स्वामी ब्रम्हानंद जी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में दर्जनों घोड़े, रबी बाजे, भांगड़ा, डीजे, बहरूपिया पार्टी,के साजबाज के साथ बज रही धुनों से गूँजते सुर सुहावने लग रहे थे। वही सैकड़ो महिलाएं अपने सिर पर सजे कलस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी।वही सैकड़ो की संख्या में आये जनप्रतिनिधि व लोग शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। यह यात्रा उनके ग्रामीण निज निवास से चल कर समूचे गांव का भ्रमण कर उनकी माता पिता की समाधि स्थल पर समाप्त हुई। तदुपरांत वही आवास के निकट गांव में ही त्याग पुरुष स्वामी ब्रम्हानंद जी महाराज की अलोकित प्रतिमा का जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, प्रतिनिधि सन्तराम राजपूत व राठ विधायक मनीषा अनुरागी व अन्य आये मेहमान जनप्रतिनिधियों ने अनावरण किया।इस बीच स्वामी जी अमर रहे के नारों ने समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। स्वामी जी की प्रतिमा के अनावरण होने पर सभी लोगो ने इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंशा की।वही इस दौरान एक दिवसीय दंगल का उटघाटन भी जिला पंचायत प्रतिनिधि सन्तराम राजपूत ने द्वारा पहलवानों का हाथ मिलवा कर किया गया।

इस बीच दूरदराज से आये प्रसिद्ध पहलवानों ने अपने दांव पेंच दिखाए जिसको देख भव्य दंगल लोगो को खूब भाया।इस बीच दो दर्जन से अधिक कुश्तियां हुई यह दंगल अत्यंत रोचक रहा। वही महोत्सव में लगे मेले में बच्चों ने झूलों का खूब आनंद उठाया तो वही मेले में लगी दुकानों में महिलाओ पुरुषों व बच्चों ने जमकर खरीददारी की। जिससे आये ब्यापारियों के चेहरों पर खुसी देखने को मिली।राठ विधायक मनीषा अनुरागी, सरीला ब्लॉक प्रमुख चंद्रिका राजपूत, मुस्कुरा ब्लॉक प्रमुख वीर नारायण राजपूत, जिला पंचायत सदस्य करण सिंह, मदन पासवान, अनुज राजपूत, महेंद्र अनुरागी, राम सजीवन यादव, विमलेश कुमारी,गोहांड ब्लाक प्रमुख अरविंद मुखिया, राठ ब्लॉक प्रमुख रामदुलारी अनुरागी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास बुधौलिया, सत्यप्रकाश राजपूत, शक्ति चौरसिया, राम आसरे राजपूत, राम औतार राजपूत, रामसेवक राजपूत, गोहांड के पूर्व चेयरमैन जीतेन्द्र राजपूत, पूर्व ब्लाक प्रमुख महेंद्र राजपूत, पूर्व ब्लाक प्रमुख द्रगपाल राजपूत, पूर्व ब्लाक प्रमुख मुकेश राजपूत, लीला राजपूत, एवं लक्ष्य परिवार की पूरी टीम सहित आसपास के प्रधानगण सहित समस्त ग्रामवासी और जनपदवासी उपस्थित रहे।

6 साल पहले पेरोल से फरार मुजरिम कभी बिहार तो कभी कोलकाता में छिपा रहा, क्राइम ब्रांच ने शामिर लुटेरे को दबोचा

● **साल 2019 में बंदूक की नोक पर लूट करने वाला गिरफ्तार।**

तंबाकू की दुकान से दोस्तों के साथ मिलकर की थी लूटपाट।

पहले बिहार के सहरसा और बाद में कोलकाता में जा छुपा।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। अपराध करने के बाद अपराधी खुद को बचाने के लिए कितनी भी जुगत कर ले लेकिन एक न एक दिन वह कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। यहां भी यही हुआ है। छह साल पहले सरस्वती विहार थाना क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर बंदूक की नौक पर तंबाकू की दुकान में लूटपाट करने वाले वांछित को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच वह कभी बिार तो कभी कोलकाता में छिपा रहा।

पुलिस के मुताबिक, उसे अगस्त 2019 में इस मामले में दो सप्ताह की पैरोल मिली थी, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और पिछले छह साल से फरार चल रहा था। आरोपित की पहचान शकरपुर के सरफराज उर्फ सोनू के रूप में हुई है जो पहले भी डकैती, लूटपाट और सेंधमारी के सात आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि वर्ष 2011 में थाना सरस्वती विहार में लूट का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपित सरफराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक तंबाकू की दुकान में बंदूक की नोक पर 30 हजार लूट लिए थे। पुलिस ने उसे मामले में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पैरोल मिलने के बाद वह फरार हो गया।

उसे पकड़ने के लिए एसीपी रमेश चंद्र लांबा की देखरेख में और इंस्पेक्टर पंकज मलिक और रोहित कुमार के नेतृत्व में टी गठित की गई थी। एएसआई सुरेश गुप्ता को सूचना मिली कि आरोपित शकूर बस्ती छिपा हुआ है। सूचना पर टीम ने 14 नवंबर को छापेमारी करते हुए उसे दबोच लिया।

पूछताछ में पता चला कि फरारी के दौरान वह बिहार के सहरसा जिले में अपने पैतृक गांव में छिपा रहा और बाद में कोलकाता चला गया, जहां उसने बैटरी रिक्शा चालक के रूप में काम किया। इसी वर्ष अगस्त में वह दिल्ली लौट आया और पकड़े जाने से बचने के लिए शकूर बस्ती में पहचान बदलकर रह रहा था।

अल फलाह ट्रस्ट के दफ्तर पर 12 घंटे से चल ही ED की रेड, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात

● **ईडी की दिल्ली में अल फलाह ट्रस्ट पर छापेमारी।**

फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में स्पेशल सेल की जांच।

दस्तावेजों की जांच और सुरक्षा कड़ी।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहम्मद रईस। जमिया नगर स्थित अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी लगातार 12 घंटे से जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है और ट्रस्ट कार्यालय के बाहर आवाजाही नियंत्रित की जा रही है। इसी कार्रवाई से जुड़े क्रम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंच गई, जहां जांच से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

स्पेशल सेल की टीम यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर रखे उस फाइल रिकॉर्ड की जांच में जुटी है, जिसमें कैंपस में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति और वाहनों का विवरण दर्ज होता है। टीम इस पूरे डेटा को अपने कब्जे में ले रही है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीम पहले से ही यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर मौजूद है, और अलग-अलग विभागों में दस्तावेजों की जांच जारी है। यूनिवर्सिटी कैंपस में बढ़ी हलचल और सुरक्षा बंदोबस्त को देखते हुए प्रशासन ने सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है। छापेमारी और सुरक्षात्मक कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोनों स्थानों पर जांच एजेंसियों की गतिविधि तेज बनी हुई है।

शिक्षा के साथ- साथ बच्चों में खेल भावना विकसित करना जरूर- विधायक श्याम धनी राही

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के बर्डपुर ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल बर्डपुर के परिसर में मंगलवार को आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग की ओर बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में खेल की भावना विकसित करना अति आवश्यक है। जिससे बच्चे विभिन्न खेल विधाओं में दक्ष होकर अपना व देश का नाम रोशन कर सकते हैं। खेल शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये भी बेहद जरूरी हैं। बर्डपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 33 वीं बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का बच्चों के खेलकूद कार्यक्रमों के साथ आगाज हुआ। बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि सदर विधायक श्याम धनी राही ने करायी। इसके बाद बच्चों ने मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी।

विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार स्पोटर्स के क्षेत्र में लगातार ऐतिहासिक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे के लिये पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद के लिए भी समय देना चाहिये। इस ग्राउंड पर खेलने वाले खिलाड़ी जीत हासिल कर तहसील , जिला ,मंडल स्तर एवं प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लें यह मेरी शुभकामनायें हैं। इस दौरान निवर्तमान मंडल अध्यक्ष नीतेश पाण्डेय ने कहा कि खेलों से बच्चों का तन एवं मन स्वस्थ होता है। वर्तमान में गांव-गांव खेल मैदान तैयार किये गये हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से तलाशा जा रहा है। खण्ड विकास अधिकारी ओम प्रकाश सिंह यादव ने कहा कि खेल बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। इसलिये बच्चों को विद्यालय में प्रतिदिन खेल गतिविधियों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान भाजपा जिला कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, शैलेंद्र कुमार मिश्रा, कलीमुल्लाह आदि मौजूद रहे।

गोबरिया में घटिया सड़क निर्माण पर ग्रामीणों का हंगामा

● **पत्नी ठेकेदार, पति सरकारी अध्यापक-फील्ड में करवाते मिले काम, ग्रामीणों से विवाद बढ़ा**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चित्रकूट। मुख्यालय से सटे गोबरिया गाँव में पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा रहे बेडीपुलिया-गोबरिया मार्ग के निर्माण को लेकर भारी विवाद की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में कथित लापरवाही, घटिया सामग्री और मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तारकोल की परत नहीं डाली गई और सीधे डामर बिछा दिया गया। इसके चलते निर्माण के कुछ ही दिनों में कई स्थानों पर सड़क उखड़ने लगी है। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से सरकारी धन की बर्बादी हो रही है और बारिश में सड़क पूरी तरह खराब होने का खतरा है।

सरकारी अध्यापक पर लगे गंभीर आरोप ग्रामीणों के मुताबिक निर्माण कार्य कराने के लिए ठेकेदार की जगह उसके पति वेद प्रकाश रलिहा, जो कि सरकारी शिक्षक बताए जाते हैं, मौके पर मौजूद थे और स्कूल का समय छोड़कर फील्ड में मजदूरों से काम करवा रहे थे। ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताई तो विवाद बढ़ गया।

'मैं तो आम जनता हूं, रास्ते से जा रहा था'- पति** ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विरोध दर्ज कराने पर वेद प्रकाश ने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकी दी।

घटना की जानकारी मिलते ही मीडिया मौके पर पहुंचा तो उन?होंने स्वयं को 'आम जनता' बताते हुए कहा कि वह तो सिर्फ 'रास्ते से गुजर रहे थे ', निर्माण कार्य से उनका कोई संबंध नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से निर्माण स्थल पर ठेकेदार की जगह काम देखते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी चित्रकूट सहित विभागीय अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजी है। उन्होंने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही जांच कर दोष तय नहीं किया गया, तो वे मजबूर होकर आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि करोड़ों रुपये की परियोजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।